



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर, 15 1986/कार्तिक 24, 1908

No. 46]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1986/KARTIKA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1986

सूचना

का० आ० 3825:— नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जग मोहन लाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे निम का थाना (राजस्थान) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (61)/86-याय]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 30th October, 1986

NOTICE

S.O. 3825.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Jag Mohan Lal Sharma Advocate, for appointment as a Notary to practise in Nim Ka thana (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(61)/86-Jud]

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

सूचना

का० आ० 3826:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री श्रीम प्रकाश गुप्ता, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे

नांसी (यू. पी.) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार काक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (72) /86-ग्या]

भार. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 4th November, 1986

NOTICE

S.O. 3826.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri O. P. Gupta Advocate, for appointment as a Notary to practise in Jhans.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(72)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

आदेश

का० आ० 3827—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार की सहमति से, आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 और धारा 30 के अधीन दण्डनीय अपराधों और भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वसे ही संव्यवहार के अन्तर्गत में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रत्यक्ष, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है।

[संख्य. 228/16/86-ए० बी० डी० (II)]

जी० सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 4th November, 1986

ORDER

S.O. 3827.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the

Central Govt. with the consent of the Government of Karnataka, hereby extends the power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for the investigation of offences punishable under sections 25 and 30 of the Arms Act, 1959 (Act 54 of 1959) and offences punishable under section 5 of the Indian Explosives Act 1884 (Act 4 of 1884) and attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[F. No. 228/16/86-AVD-II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

(आय)

का. आ. 3828:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घघ के परन्तुक के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि० बम्बई को इसकी गृह बचत योजना स्कीम और ऋण से सम्बद्ध जमा स्कीम को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है। दिनांक 18-7-1986 की पूर्ण अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित किया गया है।

[फा सं० 414/104/84-आ०क०(जा०)]

एस. राजगुरु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th October, 1986.

(INCOME TAX)

S.O. 3828.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of proviso to section 269SS of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, Housing Development Finance Corporation Limited, Bombay in respect of its Home Savings Plan Scheme, Loan Linked Deposit Scheme and Certificate of Deposit Scheme, including cumulative Interest Scheme for the purpose of the said section. The earlier notification dated 18-7-1986 is to this extent modified.

[F. No. 414/104/84-IT(INV)]

S. RAJGURU, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का० आ० 3829.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड

(iiख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ हाउसिंग डेवलपमेंट फाईनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित ऋण पत्रों को विनिर्दिष्ट करती है :—

- (1) एच० डी० एफ० सी० 12.5 प्रतिशत ऋणपत्र (1992-1996)
 - (2) एच० डी० एफ० सी० —12.5 प्रतिशत ऋण (1995)
 - (3) एच० डी० एफ० सी० — 12.5 प्रतिशत ऋण पत्र (1996)
- [सं. 6981—फा. सं. 27552/86-आ. क. (ब)]

New Delhi, the 29th October, 1986

INCOME TAX

S.O. 3829.—In exercise of the power conferred by clause (iib) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following bonds issued by the Housing Development Finance Corporation Limited, New Delhi, for the purposes of the said clause, namely :—

- (1) HDFC—12.5% Bonds (1992—1996).
- (2) HDFC—12.5% Bonds (1995).
- (3) HDFC—12.5% Bonds (1996).

[No. 6981—F. No. 275/52/86-IT(B)]

का० आ० 3830.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए नैशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "7 वर्षीय 14% आरक्षित विमोक्ष्य असंपरिवर्तनीय बंधपत्र ("क" श्रृंखला)" को विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 6982 फा. सं. 275/81/86 आ. क. (ब)]

S.O. 3830.—In exercise of the powers conferred by clause (iib) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "7-Year 14% Secured Redeemable Non-convertible Bond—(A. series)" issued by the National Hydroelectric Power Corporation Limited, New Delhi, for the purposes of the said clause.

[No. 6982 F. No. 275/81/86-IT(B)]

का. आ. 3831.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ इन्डियन पेट्रो-केमिकल्स द्वारा जारी किए गए "1986 आई. पी. सी. एस.—14% प्रतिशत आरक्षित मोचनीय असंपरिवर्तनीय ऋण पत्रों को विनिर्दिष्ट" करती है।

[सं. 6983—फा. सं. 275/109/86—आ. क. (ब)]

बा. नागराजन, निदेशक

S.O. 3831.—In exercise of the powers conferred by clause (iib) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "1986—IPCL—14% Secured Redeemable non-convertible Bonds" issued by the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Baroda, for the purposes of the said clause.

[No. 6983 F. No. 275/109/86-IT(B)]

B. NAGARAJAN, Director.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 3832:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 21) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो नैशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किये जाने वाले केवल दस करोड़ रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों "आई०डी०बी०आई०" ऋण 10 करोड़ रु० (1986)—प्रथम श्रृंखला के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 40/86—स्टाम्प—फा. सं. 33/46/86—बि. कर]

बी० आर० मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 3832.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory Notes "IDBI" loan Rs. 10 crores (1986)—1st Series" of the value of ten crores of rupees only to be issued by the National Small Industries Corporation, Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 40/86-Stamp. F. No. 33/46/86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

का. आ. 3833.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बोर्ड की अधिवृत्त सं. 4306 (फा. सं. 261/13/81 आ० का. न्याय, दिनांक 13-11-81) सं. 4448 (फा. सं. 261/6/82 आ० का. न्याय, दिनांक 1-2-82), सं. 4041 (दिनांक 7-10-82 तथा 4962 (फा. सं. 261/6/82 आ० का. न्याय, दिनांक 10-11-82 और सं. 6518 (फा. सं. 279/143/84 आ० का. न्याय, दिनांक 29-11-85) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेजों के प्रपीलीय सहायक आयकर भावुक के लिए निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिनपर क्षेत्राधिकार आयकर लागू

(अपील) में निहित है, अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, बाड़ों, और जिलों में आयकर के निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के सम्बन्ध में अपने कार्य करेंगे:—

अनुसूची

क्रम. सं.	रेंज	आयकर परिमण्डल / बोर्ड / जिला
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त इन्दौर रेंज, इन्दौर	1. इन्दौर के सभी आयकर अधिकारी 2. सहायक आयुक्त संवा गुल्फ, इन्दौर 3. आयकर अधिकारी, धार 4. आयकर परिमण्डल, खण्डवा 5. आयकर अधिकारी, खरगोन
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, उज्जैन रेंज उज्जैन,	1. आयकर परिमण्डल, उज्जैन 2. आयकर परिमण्डल, रतलाम 3. आयकर परिमण्डल, मन्सौर 4. आयकर परिमण्डल, तीमन 5. आयकर परिमण्डल, देवास
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, भोपाल रेंज, भोपाल ।	1. भोपाल के सभी आयकर अधिकारी 2. भोपाल में मुख्यालय के साथ आयकर अधिकारी सेहोर 3. आयकर परिमण्डल इटारसी 4. आयकर परिमण्डल बेतल 5. आयकर परिमण्डल, विदिशा
4.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ग्वालियर रेंज, ग्वालियर ,	1. ग्वालियर के सभी आयकर अधिकारी 2. आयकर परिमण्डल, गुना 3. आयकर परिमण्डल, शिवपुरी 4. आयकर परिमण्डल, मुरैना

2. जहाँ कहीं कोई आयकर परिमण्डल बाड़ें जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तर्गत कर दिया गया हो, वहाँ उस आयकर परिमण्डल, बाड़ें या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना की तारीख से तत्कालपूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलों जिसके अधिकारी क्षेत्र से उक्त आयकर परिमण्डल, बाड़ें या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तर्गत किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, बाड़ें और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तर्गत किया गया है।

यह आदेश दिनांक 1-10-1986 से लागू होगा।

[सं. 6942/86 (फा. सं. 261/27/86 आ. का. न्या. 7)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30th September, 1986

S.O. 3833.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of

1961) and in partial modification of Board's notification No. 4306 (F.No.261/13/81-ITJ dated 13-11-81), No. 4448 (F.No. 261/6/82-ITJ dated 1-2-82), No.4041 (dt.7-10-82) and 4962 (F.No. 261/6/82-ITJ dt.10-11-82) and No. 6518 dt. 29-11-85 (F.No.279/143/84-ITJ), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column No. 2 thereof excluding all persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-Tax (Appeals):

SCHEDULE

S.No.	Range	Income-tax Circle, Wards and Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Indore Range, Indore.	1. All ITOs at Indore 2. A.C.E.D. Indore. 3. I.T.O. Dhar. 4. I.T. Circle, Khandwa. 5. I.T.O. Kharagone,
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ujjain Range, Ujjain.	1. I.T.Circle, Ujjain. 2. I.T.Circle, Ratlam. 3. I.T.Circle, Mandsaur. 4. I.T.Circle, Neemuch. 5. I.T.Circle, Dewas.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bhopal Range, Bhopal	1. All I.T.Os at Bhopal 2. I.T.O.Sehore with Hqrs. at Bhopal. 3. I.T.Circle, Itarsi. 4. I.T.Circle, Betul. 5. I.T.Circle, Vidisha.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Gwalior Range, Gwalior.	1. All I.T.Os at Gwalior. 2. I.T.Circle, Guna. 3. I.T.Circle, Shivpuri. 4. I.T.Circle, Morena.

2. Wherever on Income-tax circle, wards, district or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that I. T. Circle, wards or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that I. T. Circle, ward or district or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This order shall take effect from 1-10-1986.

[No. 6942/86 (F. No. 261/27/86-ITJ)]

का. प्रा. 3834.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की दिनांक 7-7-1978 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 2302 (फा. सं. 261/7/78-आ. क. (न्या.)). दिनांक 14-1-82 की अधिसूचना सं. 4413 (फा. सं. 261/27/81 आ. का. (न्या.)) और दिनांक 14/15-9-84 की अधिसूचना सं. 5988 (फा. सं. 261/17/84 आ. क. (न्या.)) में आंशिक संशोधन करने हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निवेदन देता है कि नीचे दी गई अनुसूची

के सम्बन्ध (1) में विनिर्दिष्ट प्रभारों के आयकर आयुक्त (अपील) सम्बन्ध (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमंडलों और जिलों में आयकर, अथवा अधिकार अथवा ब्याज कर के लिए निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्य निर्वहण करेंगे जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कम्पनी (अनुलाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (i) और ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (i) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं, और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के सम्बन्ध में भी, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा 2 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निर्देश दिया है या भविष्य में निर्देश दे।

अनुसूची

मुख्यालयों सहित प्रभार	आयकर वार्ड / परिमंडल
1	2
1. आयकर आयुक्त (अपील) भोपाल	निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्ड / परिमंडल:— (i) नि. स. आ., भोपाल रेंज, भोपाल। (ii) नि. स. आ. ग्वालियर रेंज, ग्वालियर। (iii) नि. स. आ. (कर-नि.) रेंज, ग्वालियर। (iv) नि. स. आ. (कर-नि.) रेंज, भोपाल
2. आयकर आयुक्त (अपील) इन्दौर	सम्बन्धित श्रृंखला परिमंडल, आयकर परिमंडल, धार और 'न' वार्ड, इन्दौर को छोड़कर, निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्ड / परिमंडल:— (i) नि. स. आ., रेंज-I, इन्दौर (ii) नि. स. आ. (निर्वाण) रेंज, इन्दौर
3. आयकर आयुक्त (अपील) II इन्दौर	निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्ड / परिमंडल:— (i) नि. स. आ., रेंज-II, इन्दौर, (ii) नि. स. आ. उज्जैन रेंज, उज्जैन। (iii) नि. स. आ. रेंज-I इन्दौर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सम्बन्धित श्रृंखला परिमंडल, आयकर परिमंडल, धार और 'न' वार्ड, इन्दौर।
4. आयकर आयुक्त (अपील) जबलपुर	आयकर आयुक्त, जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वार्ड / परिमंडल, सम्बन्धित श्रृंखला परिमंडलों सहित।

जहाँ कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र से अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तर्गत कर दिया गया हो, वहाँ उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस तारीख से तत्काल पूर्व, उस अधिकार क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) के समस्त विचारणीय अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त आयकर परिमंडल, वार्ड, अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तर्गत किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस अधिकार क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड या जिला या रेंज या उसका कोई भाग अन्तर्गत किया गया है।

यह अधिसूचना 1-10-1986 से लागू होगी।

[सं. 6941/86 (फा.स. 261/26/86-आ. क. (स्या))]

मुरेंद्र पाण्डे, अधीक्षक सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

S.O. 3834—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of Boards earlier notification No. 2302 dt. 7-7-1978 (F.No.261/77-ITJ) No. 4413 (F. No. 261/27/81-ITJ dt. 14/1/82), No. 5988 (F.No. 261/17/84-ITJ dt. 14/15-9-84), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest Tax in the Income-tax Wards, Circles & Districts specified in the corresponding entries in the column No. (2) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in classes (a) to (h) of Sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961 in Sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in Sub-section (1) of Section 15 of Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of Sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with Head Quarters	Income-tax Wards/Circles
1	2
1. Commissioner of Income-tax (Appeals), Bhopal.	All wards/circles falling within the jurisdiction of:— (1) IAC, Bhopal Range, Bhopal. (2) IAC, Gwalior Range, Gwalior. (3) IAC (Asstt.) Range, Gwalior (4) IAC (Asstt.) Range, Bhopal.
2. Commissioner of Income-tax (Appeals), Indore.	All ward/circles excluding Estate Duty Circle, Income-tax Circle, Dhar AND 'C' Ward, Indore falling within the jurisdiction of:— (1) IAC, Range-I, Indore. (2) IAC (Asstt.), Range, Indore

1	2
3. Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Indore	All wards/circles falling within the jurisdiction of: (1) IAC, Range-II Indore. (2) IAC, Ujjain Range, Ujjain. (3) Estate Duty Circle, Income-tax Circle, Dhar and 'C' Ward, Indore falling within the jurisdiction of IAC, Range-I, Indore.
4. Commissioner of Income-tax (Appeals), Jabalpur.	All wards/circles including E.D. Circles falling within the jurisdiction of C.I.T., Jabalpur.

Whereas the Income-tax Circle, Ward or district or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, ward or district or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge from whom that Income-tax circle, ward or district or Range or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, ward or district or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-10-1986.

[No. 6941/86/F.No. 261/26/86 -IT(J)]

SURENDER PAUL, Under Secy.

Central Board of Direct Taxes

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3835—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर. डी. देशपांडे को फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है, तथा 16-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर. डी. देशपांडे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2-14/86-आर. आर. बी.]

(Deptt. of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd October, 1986

S.O. 3835.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R. D. Deshpande as the Chairman of the Fatehpur Kshetriya Gramin Bank, Fatehpur and specifies the period commencing on the 16-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri R. D. Deshpande shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-14/86-RRB]

का. आ. 3836—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के. यू. याज्ञिक को सुलतानपुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 10-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के. यू. याज्ञिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2/13/86-आर. आर. बी.]

S.O. 3836.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri K. U. Yagnik as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur and specifies the period commencing on the 10-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri K. U. Yagnik shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-13/86-RRB]

का. आ. 3837—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ओ. पी. गर्ग को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-9-85 को समाप्त हो गई है, 1-10-85 से प्रारम्भ होकर 9-8-86 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 2/13/86-आर. आर. बी.]

S.O. 3837.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby reappoints Shri O. P. Garg whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 30-9-85 as the Chairman of Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur for a further period commencing from 1-10-85 and ending with 9-8-86.

[No. F. 2-13/86-RRB]

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3838—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री रामचरण पांडेय को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत वर्धमान ग्रामीण बैंक, बुर्दवान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 22-10-1985 को समाप्त हो गयी है, 23-10-1985 से प्रारम्भ होकर 18-7-1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 2-85/82-आर. आर. बी.]

New Delhi, the 27th October, 1986

S.O. 3838.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby reappoints Shri Ramcharan Pandey whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 22-10-1985 as the Chairman of Bardhaman Gramin Bank, Burdwan for a further period commencing from 23-10-85 and ending with 18-7-1986.

[No. F. 2-85/82-RRB]

New Delhi, the 28th October, 1986

का. भा. 3839—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन. एन. चक्रवर्ती को वर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्दवान (प. बंगाल) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 19-7-86 से प्रारम्भ होकर 31-7-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन. एन. चक्रवर्ती अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2/85/82-आर. आर. बी.]

S.O. 3839.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri N. N. Chakravorty, Chairman, Bardhaman Gramin Bank, Burdwan (W.B.) and specifies the period commencing on the 19-7-86 and ending with the 31-7-89 as the period for which the said Shri N. N. Chakravorty shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-85/82-RRB]

का भा. 3840—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे.आर. नकवी को गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 12-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जे.आर. नकवी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-21/86-आर.आर. बी.]

च.वा. मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 3840.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri J. R. Naqvi as the Chairman of Gomti Gramin Bank, Jaunpur (Uttar Pradesh) and specifies the period commencing on the 12-8-1986 and ending with the 31-8-1989 as the period for which the said Shri J. R. Naqvi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-21/86-RRB]

C. W. MIRCHANDANI, Director.

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

का भा. 3841—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 की धारा 3 की उपधारा (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री के. एक. भार्गव प्रधानाचार्य, रिजर्व बैंक, स्टाफ कालेज, मद्रास-600018 को श्री ओ. पी. सोहानी के स्थान पर, एतद्वारा आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/2/86-बी. ओ.-1]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

S.O. 3841.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri K. N. Bhargava, Principal, Reserve Bank Staff College, Madras as a Director of Andhra Bank vice Shri O. P. Sodhani.

[No. F. 9/2/86-B.O. I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. भा. 3842—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर उक्त निगम द्वारा 25 नवंबर, 1986 को जारी किए जाने वाले और 25 नवंबर, 2001 को परिपक्व होने वाले बांडों पर देय ब्याज की दर एतद्वारा 11 प्रतिशत (ग्यारह प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा. सं. 6(10)/86-आई.एफ.1]

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3842.—In pursuance of Sub-section 2 of section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 11 percent (eleven percent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 25th November, 1986 and maturing on 25th November, 2001.

[F. No. 6(10)/86-IF-I]

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का. भा. 3843—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर उक्त निगम द्वारा 1 जनवरी, 1987 से 21 दिसंबर, 1987 की अवधि के लिए जारी किए जाने वाले बांडों पर देय ब्याज की दर एतद्वारा 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा. सं. 6(27)/86-आई.एफ.-I]

पी. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3843.—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India hereby, fixes 10 percent (Ten percent) per annum as the rate of interest payable on the bonds, having currency during the period 1st January 1987 to 31st December, 1987, to be issued by the said Corporation.

[F. No. 6(27)/86-IF-I]

P. K. MALHOTRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का०आ० 3844 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (ख) (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री गुडिपति गोपाल कृष्णामूर्ति, विशेष सहायक, बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद मुख्य शाखा को दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 से 30 अक्टूबर, 1989 तक बैंक आफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[स एफ० 15/5/82-आई० आर०]

सतपाल भाटिया, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3844.—In pursuance of sub-clause (b)(i) of clause 3, read with sub-clause (2) of clause 9, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Gudipaty Gopala Krishna Murthy, Special Assistant, Bank of India, Hyderabad Main Branch, as a Director on the Board of Directors of the Bank of India with effect from 31st October, 1986 to 30th October, 1989.

[No. F. 15/5/82-IR]

S. P. BHATIA, Under Secy.

कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मध्य प्रदेश

इंदौर, 27 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना संख्या 12/86

का०आ० 3845 :—मध्यप्रदेश समाहर्तलिय इंदौर के निम्नलिखित अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

1. श्री एम० एच० जोशी 30-9-86 (अपराह्न)
2. श्री डी० पी० तिवारी 30-9-86 (अपराह्न)

[फा० सं० II (3) 2-गोप/86]

एस. वी. रामाकृष्णन, समाहर्त

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Indore, the 27th October, 1986

NOTIFICATION NO. 12/86

S.O. 3845 :—The following Superintendent of Central Excise Gr. 'B' of Central Excise Collectorate, Indore having attained the age of Superannuation retired from Govt. service on the dates as shown against each:—

S. No.	Name of the Officer	Date
1.	Shri M.H. Joshi	30-9-86 (AN)
2.	Shri D.P. Tiwari	30-9-86 (AN)

[C. No. II (3) 2-CON/86]

S.V. RAMAKRISHNAN, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1986

का०आ० 3846 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 1043 G of II/86—2

के उपनियम (4) के अनुसरण में वाणिज्य व वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

वाणिज्य मंत्रालय :

1. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, जनपथ "ए" बैरेक्स, नई दिल्ली-110001.
2. क्षेत्रीय कार्यालय, नियंत्रक, आयात-निर्यात श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)

वस्त्र मंत्रालय :

1. नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लि० (गुजरात) अहमदाबाद।

[फाइल सं० ई-11011/22/86-हिन्दी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 16th July, 1986

S.O. 3846.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Commerce and Ministry of Textiles, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Ministry of Commerce :

1. Central Cottage Industries Corporation of India Ltd., Janpath 'A' Barracks, New Delhi-110001.
2. Office of the Controller of Imports and Exports, Srinagar (Jammu & Kashmir)

Ministry of Textiles :

1. National Textiles Corporation Ltd., (Gujarat), Ahmedabad.

[File No. E-11011/22/86-Hindi]

VED PRAKASH, Director

कार्यालय संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

[फा० सं०—एडीसी/आई/यूडीईए/84/एएम 85/ए एलएम-I/सीएए]

निरस्त आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1986

का० आ० 3847 :—मैसर्स अब्दुल शकूर एंड संस, 3/डी-II, कोहना मुगल, कुली खान का इमामबारा, मुरादाबाद को 41 662 एम टी हास स्क्रैप का आत करने के लिए अग्रिम आयात लाइसेंस सं-पो/कि3080729 डि० डि० 9-8-84 रु 4,84,600/- प्रदान किया गया था :

कर्म ने उक्त लाइसेंस की एकपत्र नियंत्रण प्रयोजन कापी प्रस्तुत की है तथा कहा है कि अग्रिम लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनकापी कहीं अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस 4,84,600 रु की थी राशि के लिए जारी किया गया था।

आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9(डी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त अधिम साइसेंस को निरस्त करने के आदेश देता हूँ।

[फाइल सं.-एडोशो/आई/यूडी/ईएम/84/एम. 85/ए.एल.एस-I]

सी एल. ए/812

डा. आर. के. धवन,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

कृते संयुक्त मु. नि.-आयात एवं

निर्यात

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS
(Central Licensing Area)

New Delhi, the 16th July, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3847.—M/s. Abdur Shakoor & Sons, 3/D. II Kohna Mughal Kuli Khan Ka Iman Bara, Moradabad were granted advance licence No. P/K/3080729 dt. 9-8-84 for Rs. 4,84,600 for import of 41.662 M. T. of Brass Scrap.

The firm have surrendered the Exchange Control Purpose copy of the said licence intimating that the Customs Purposes copy of the advance licence has been misplaced. The amount for which the licence was issued is Rs. 4,84,600.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(d) of Import (Control) order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, I hereby order cancellation of the said advance licence.

[F. No. Adv/Lic/UDS/84/AM. 85/ALS. I/CLA/812]
(DR.) R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of I & E
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1986

का. भा. 3848.—राजनयिक और कौमलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत का राजदूतावास, रियाद में सहायक श्री आर. के. कपूर को 12-9-86 से कौमली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[टी. 4330/1/86]

के. नागराजन, अवसरसचिव (कौमली)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 3848.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. K. Kapoor, Assistant in the Embassy of India, Riyadh to perform the duties of Consular Agent with effect from 12-9-86.

[T. 4330/1/86]

K. NAGARAJAN, Under Secy. (Consular)

1043 GI/86—2

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. भा. 3849:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण को, उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के भाग क प्रस्ताव-III के उपबंध अब लागू नहीं होते हैं, के निरस्तकरण को अधिपूजित करती है।

[सं. 16/12/86-एम. 3]

एल. सी. गोयल, अवसर सचिव

अधिसूचना सं० 16/12/86 एम.-III का अनुलग्नक

क्रम सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण संख्या
1.	मै. गोदावरी सुगर मिल्स, लि.,	फज्जबोय बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, पो. ब. नं. 122, "ए" फोर्ट बम्बई-400023	1231/75
2.	मै. गोदावरी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.,	—परीर—	1232/75
3.	मै. केपन मेटल प्रोडक्शन प्रा. लि.,	(भूत पूर्व भावना कैपिटल प्रा. लि.)	लक्ष्मी इन्सुरेन्स बिल्डिंग 540/70 सर किरोजी-माडू मेडना रोड, बम्बई-1

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3849.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M. III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

Annexure to the Notification No. 16/12/86. M-III

S. No.	Name of the Undertakings	Registered Address	Registration
1.	M/s. Godavari Sugar Mills Ltd.	Fazabhooy Building, Mahatma Gandhi Road, P.B. No. 122-A, Fort Bombay-400 023.	1231/75
2.	M/s. Godavari Investment & Finance Corporation Ltd.	—do—	1232/75
3.	M/s. K. S. Mital Products Private Ltd. (Formerly Bhavana Chemicals Private Ltd.)	Laxmi Insurance Building, Sir Phirozshah Matha Road, Bombay-1	540/70

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 1986

पृ. 1-11

का. आ. 3850 --भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 6 अक्टूबर, 1984 पृष्ठ क्रमांक 2919 और 2020 का.आ. संख्या क्रमांक 0-12016/133/83-प्रोड के अन्तर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 3148 दिनांक 6 अक्टूबर 1984 के अन्तर्गत-पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव-च-होली तहसील-हवेली जिला-पुणे महाराष्ट्र के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पार्श्व लाईन विछाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से भ्रम न रहा है। अब अतः, निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा 6 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग—1

कालम II पढ़ें

कालम 1 के लिये

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च-होली	134	1 + 4	00-32-40	च-होली	134	का भाग	00-47-00
	134	4	00-36-54				
	302	1	00-16-20		302	"	00-25-00
	303	1	00-43-06		303	"	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	का भाग	00-27-00		305	"	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	"	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	"	00-47-00
	352	1	00-70-20		352	"	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3 + 4	00-32-40		406	"	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	"	00-39-00
	409	का भाग	00-16-20		409	"	00-45-00
	410	"	00-39-60		410	"	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	"	00-12-00
	428	1	00-06-66		428	"	00-22-00
	430	3	00-18-00				
	430	4	00-06-00		430	"	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00		432	"	00-18-00
	432	6	00-05-94				
	433	2	00-16-25		433	"	00-19-00
	433	3	00-10-08				
	435	1-अ	00-01-62		435	"	00-27-00
	435	1-ब	00-15-30				
	435	2	00-05-40				

भाग—1

कालम II पढ़ें

कालम 1 के लिये

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च—होली	443	2-4	00-14-76	च—होली	443	का भाग	00-39-00
	444	का भाग	00-29-62		444	"	00-52-00
	445	"	00-25-92		445	"	00-34-00
	668	1+07	00-61-60		668	"	00-39-00
	669	का भाग	00-28-44		669	"	00-25-00
	670	"	00-39-60		670	"	00-41-00
	711	(1-03)	00-06-90		711	"	00-09-00
	712	का भाग	00-18-50		712	"	00-20-00
	713	"	00-21-60		713	"	00-23-00
	714	"	00-32-40		714	"	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	"	00-22-00
	737	1	00-06-39		737	"	00-09-00
	737	2	00-04-50				
	738	2	00-05-00				
	738	3			738	"	00-09-00
	738	4	00-03-39				
	739	का भाग	00-34-40		739	"	00-68-00
	798	1 }	00-08-64				
	798	2 }	00-05-58		798	"	00-17-00
	798	3 }	00-21-60				
	799	1	00-14-76		799	"	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	"	00-14-00
	803	का भाग	00-09-00		803	"	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	"	00-38-00
	811	का भाग	00-63-36		811	"	00-32-00

भाग—II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च—होली	306	का भाग	00-02-00
	353	"	00-22-00
	407	"	00-01-00
	431	"	00-02-00
	718	"	00-13-00
	719	"	00-07-00

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3850.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. 0-12016/133/83-Prod date 6-10-84 published under S.O. No. 3148 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 2919 & 2920 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages Charholi for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and the afore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub Section (i) referred to above.

Read (Col.—II).

For (Col.—I).

PART—I

Village	G. No.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Charoli.	134	1+4	00-32-40	Charoli	134	(pt)	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	(pt)	00-25-00
	302	1	00-16-10				
	303	1	00-43-06		303	(pt)	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	(pt)	00-27-00		305	(pt)	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	(pt)	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	(pt)	00-47-00
	352	1	00-70-20		352	(pt)	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3+4	00-32-40		406	(pt)	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	(pt)	00-39-00
	409	(pt)	00-16-20		409	(pt)	00-45-00
	410	(pt)	00-39-60		410	(pt)	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	(pt)	00-12-00
	428	1	00-06-60		428	(pt)	00-22-00
	430	3	00-18-00				
	430	4	00-06-00		430	(pt)	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00				
	432	6	00-05-94,		432	(pt)	00-18-00
	433	2	00-16-25				
					433	(pt)	00-19-00
	433	3	00-10-08				
	435	1-A	00-01-62				
	435	1-B	00-15-30		435	(pt)	00-27-00
	435	2	00-05-40				
	443	2+4	00-14-76		443	(pt)	00-39-00
	444	(pt)	00-29-62		444	(pt)	00-52-00
	445	(pt)	00-25-92		445	(pt)	00-34-00
	668	1+7	00-61-60		668	(pt)	00-39-00
	669	(pt)	00-28-44		669	pt	00-25-00
	670	(pt)	00-39-60		670	(pt)	00-41-00
	711	1+03	00-06-90		711	(pt)	00-09-00
	712	(pt)	00-18-50		712	(pt)	00-20-00
	713	(pt)	00-21-60		713	(pt)	00-23-00
	714	(pt)	00-32-40		714	(pt)	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	(pt)	00-22-00
	737	1	00-06-39				
					737	(pt)	00-09-00
	737	2	00-04-50				
	738	2					
	738	3	00-09-00		738	(pt)	00-09-00
	738	4	00-03-39				
	739	(pt)	00-34-40		739	(pt)	00-68-00
	798	1	00-08-64				
	798	2	00-05-58		798	(pt)	00-17-00
	798	3	00-21-60				

PART—I

Village	G.No.	H.No.	Area	Village	G.No.	H.No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Charoli	799	1	00-14-76		799	(pt)	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	(pt)	00-14-00
	803	2(pt)	00-09-00		803	(pt)	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	(pt)	00-38-00
	811	(pt)	00-63-36		811	(pt)	00-32-00

PART—II

Village	G.No.	H.No.	Area
Charoli	306	(pt)	00-02-00
	353	(pt)	00-22-00
	407	(pt)	00-01-00
	431	(pt)	00-02-00
	718	(pt)	00-13-00
	719	(pt)	00-07-00

[No. O-12016/133/83-Prod-I]
P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

शुद्धि पत्र

क्र. घा. 3851:— भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 पृष्ठ क्रमांक 4586 और 4587 का. आ. संख्या क्रमांक ओ-12016/133/83 प्रोड के अंतर्गत भारत सरकार, उच्च मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग), को अधिसूचना संख्या क्रमांक 4448 दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 के अंतर्गत—पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिनियम का अर्थ) अधिनियम 1962 की धारा 3 उपधारा (i) के अर्जित वर्णित गांव—बहोली सहित—द्वेजी जिला—पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के पहले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अनार्डिनेट बदलने से प्रभन रहा है, अब अब निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग I

कालम II पढ़ें				कालम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8
बहोली	134	1+4	00-32-40	बहोली	134	का भाग	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	"	00-25-00
	302	1	00-16-20				
	303	1	00-43-06		303	"	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	का भाग	00-27-00		305	"	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	"	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	"	00-47-00
	352	1	00-70-00		352	"	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3+4	00-32-40		406	"	00-47-00
	408	2	00-21-80		408	"	00-39-00
	409	का भाग	00-16-20		409	"	00-45-00
	410	"	00-39-60		410	"	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	"	00-12-00
	428	1	00-06-68		428	"	00-22-00
	430	3	00-18-00				

भाग 1

कालम II पदे				कालम 1 के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
बहोली	430	4	00-06-00	बहोली	430	का भाग	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00		432	"	00-18-00
	432	6	00-03-94				
	433	2	00-16-25		433	"	00-19-00
	433	3	00-10-08				
	435	1=घ	00-01-82		435	"	00-27-00
	435	1=ख	00-15-30				
	435	2	00-05-40				
	443	2+4	00-14-76		443	"	00-39-00
	444	का भाग	00-29-62		444	"	00-52-00
	445	"	00-25-92		445	"	00-34-00
	668	1+7	00-61-60		668	"	00-39-00
	669	का भाग	00-28-44		669	"	00-25-00
	670	"	00-39-60		670	"	00-41-00
	711	(1+3)	00-06-90		711	"	00-09-00
	712	का भाग	00-18-50		712	"	00-20-00
	713	"	00-21-60		713	"	00-23-00
	714	"	00-32-40		714	"	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	"	00-22-00
	737	1	00-06-39		737	"	00-09-00
	737	2	00-04-50				
	738	2}	00 09 00				
	738	3}			738	"	00-09-00
	738	4	00-03-39				
	739	का भाग	00-34-40		739	"	00-68-00
	798	1}	00-08-64				
	798	2}	00-05-58		798	"	00-17-00
	798	3}	00-21-60				
	799	1	00-14-76		799	"	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	"	00-14-00
	803	का भाग	00-09-00		803	"	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	"	00-38-00
	811	का भाग	00-63-36		811	"	00-12-00

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
बहोली	306	का भाग	00-02-00
	353	"	00-22-00
	407	"	00-01-00
	431	"	00-02-00
	718	"	00-13-00
	719	"	00-07-00

ह. सभम प्राधिकारी

[स. O-12016 / 133 / 83 - प्रोड]

New Delhi, the 28th October, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 3851.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/133/83-Prod., date 10-12-83 published under S.O. No. 4448 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at pages 4586 & 4587 issued under Section 3, Sub-section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages Charholi for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under Section 3, Sub-section (i) referred to above :

SCHEDULE

Read (Col II)

PART-I

For (Col-I)

Village	G. No.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
Charoli	134	1+4	00-32-40	Charoli	134	(Pt)	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	(Pt)	00-25-00
	302	1	00-16-20				
	303	1	00-43-06		303	(pt)	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	(pt)	00-27-00		305	(pt)	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	(pt)	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	(pt)	00-47-00
	352	1	00-70-20				
					352	(pt)	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3+4	00-32-40		406	(pt)	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	(pt)	00-39-00
	409	(pt)	00-16-20		409	(pt)	00-45-00
	410	(pt)	00-39-60		410	(t)	00-36-00
	414	1	00-03-64		414	(pt)	00-12-00
	428	1	00-05-66		428	(pt)	00-22-00
	430	3	00-18-00				
	430	4	00-05-00		430	(pt)	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00				
					432	(pt)	00-18-00
	432	6	00-05-94				
	433	2	00-16-25				
					433	(pt)	00-19-00
	433	3	00-10-08				
	435	1-A	00-01-62				
	435	1-B	00-15-30		435	(pt)	00-27-00
	435	2	00-05-40				
	443	2+4	00-14-76				
	444	(pt)	00-29-62		443	(pt)	00-39-00
	445	(pt)	00-25-92		444	(pt)	00-52-00
	668	1+07	00-61-60		445	(pt)	00-34-00
	669	(pt)	00-28-44		668	(pt)	00-39-00
	670	(pt)	00-39-60		669	(pt)	00-25-00
	711	(1+3)	00-06-90		670	(pt)	00-41-00
	712	(pt)	00-18-50		711	(pt)	00-09-00
	713	(pt)	00-21-60		712	(pt)	00-20-00
	714	(pt)	00-32-40		713	(pt)	00-23-00
	736	3	00-14-94		714	(pt)	00-45-00
	737	2	0-04-39		736	(pt)	00-22-00
	737	2	0-04-50		737	(pt)	00-09-00
	738	2					
			00-09-00		738	(pt)	00-09-00
	738	3					
	738	4	00-03-39				
	739	(pt)	00-34-40		739	(pt)	00-68-00
	798	1	00-08-64				
	798	2	00-05-58		798	(pt)	00-17-00
	798	3	00-21-60				

Village	G. N.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
Charoli—(contd.)	799	1	00-14-76	Charoli (contd.)	799	(pt)	00-13-03
	800	4	00-01-80		800	(pt)	00-14-00
	803	2(pt)	00-09-00		803	(pt)	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	(pt)	00-38-00
	811	(pt)	00-63-36		811	(pt)	00-32-00

PART-II

Village	G.No.	H. No.	Area
Chroll	306	(pt)	00-02-00
	353	(pt)	00-22-00
	407	(pt)	00-01-00
	431	(pt)	00-02-00
	718	(pt)	00-13-00
	719	(pt)	00-07-00

Sd./

(Competent Authority)

[No. O-12016/133/31-Part I]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. प्रा. 3851.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन.एन.सी.आर. से एस.एम.सी. टी. एक. तक पेट्रो-लियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत :

अनुसूची

एस. एन. सी. आर. से एस. एम. सी. टी. एक. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं	हेक्टर	आर.	सेंटीयर
बलोल	1757	0	12	60
	1760	0	07	68
	1652	0	07	20
	1762	0	01	32

[सं O-12016/186/86 ओ एन जो-डी-4]

New Delhi the 29th October, 1986

S.O. 3852.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCR to S. S. CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said Land, to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makaroura Road, Badodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from ROU from SNCR to S.S. CTF.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana				
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Balol	1757	0	12	60
	1760	0	07	68
	1652	0	07	20
	1762	0	01	32

[No. O-12016/186/86—ONG-D 4]

का० आ० 3853.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 15 से एस.आई.पी. 34 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रति होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुवाच्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आशेष सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

अनसूची

कूप नं० 15 से एस.आई.पी. 34 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी				
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर आर.	सेंटियर	
थोल	1423/पी	0	55	00

[सं० O-12016/185/86-ओ एन जी-डी-4]

1043 GI/86—3

S.O. 3853.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P. 34 in Gujarat State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from well No. 15 to S.I.P. 34,

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Thol	1423/P	0	55	00

[No. O-12016/185/86-ONG. D 4]

का.आ. 3854.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० करजासन-1 से कलोल-126 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुवाच्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आशेष सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

अनुसूची

कूप नं. करजीसन-1 से कलोल-126 तक पाइप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
घुमासन	670	0	18	30
	669	0	3	0
	671	0	18	90
	666	0	12	0
	733	0	4	50
	720	0	15	00
	721	0	18	00
	722	0	7	80
	114	0	14	80
	103	0	12	00
	113/2	0	4	50
	104/1	0	12	0
	106	0	5	40
	105	0	5	40
	97	0	4	50
	96	0	5	40
	कार्ट ट्रैक	0	0	90
	95/5	0	6	0
	134	0	12	15
	175	0	12	30

[सं. ओ-12016/189/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3854.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Karjisan-1 to Kalol-126 in Gujarat State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from well No. Karjisan-1 to Kalol-126

State : Gujarat Taluka : Kadi District : Mehsana

Village	Survey No.	Hectares	Area	Centiare
Ghumasan	670	0	18	30
	669	0	3	0
	671	0	18	90
	666	0	12	0
	733	0	4	50
	720	0	15	00
	721	0	18	00
	722	0	7	80
	114	0	14	80
	103	0	12	00
	113/2	0	4	50
	104/1	0	12	0
	106	0	5	40
	105	0	5	40
	97	0	4	50
	96	0	5	40
	Cart Track	0	0	90
	95/5	0	6	0
	134	0	12	15
	175	0	12	30

[N.Y. O-12016/189/86-ONG D 4]

का.भा. 3855.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.सी. ए. से एस.एन.बी.ए. ने एस.एन.टी. टी. एक. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी जगहों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन.एन.डी. अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आदेश एन.डी. द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और वेदभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वाडोदरा-9 को सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच.एन.सी.ए. से एम.एन.बी.ए. से एस. एच. सी.टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
संधारा	492	00	08	28
	562	0	23	16

[सं. ओ-12016/176/86-ओ.एन.जी.डी-4]

S.O. 3855.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCA to SNBA to S.S.CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCA to SNBA to S.S. CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cent- re
Sandhar	492	00	08	28
	562	0	23	16

[N. O-12016/176/86-ONG-D4]

का.आ. 3856—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी. एस.नं. एस. के.ए. ए. बी. से सी.टी. एफ. कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि सभी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी.एस. नं. एस. के.ए.बी. से सी.टी.एफ. कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कड़ी	1643	0	9	75

[सं. ओ-12016/177/86-ओ.एन.जी.डी-4]

S.O. 3856.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Drill Site No. SKAB to C.T.F. Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Drill site No. SKAB to CTF Kadi.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kadi	1643	0	9	75

[No. O-12016/177/86—ONG-D 4]

का.आ. 3857.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोल आयल वाल्व प्लेट फार्म से आई.पी.एस. दक्षिण कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोल आयल वाल्व प्लेट फार्म से आई. पी.एस. दक्षिण कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कड़ी	1857	0	6	00
	कार्ट ट्रैक	0	6	30
	1953	0	2	55
	1976	0	3	60
	1977	0	4	50
	1978	0	2	00

[सं. ओ-12016/180/86-ओ.एम.पी.-4]

S.O. 3857.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sokoil Valve Platform to I.P.S. South Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Sokoil Valve platform to IPS. South Kadi

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kadi	1857	0	6	00
	Cart Track	0	6	30
	1953	0	2	55
	1976	0	3	60
	1977	0	4	50
	1978	0	2	00

[No. O-12016/180/86—ONG-D 4]

का.आ. 3858.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के-397 से जी.ओ.एस.-V तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के० 397 से जी०जी०एस० V तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आरे०	सेन्टीयर
वडावस्वामी	100	0	09	00
	107	0	13	50
	106	0	07	50
	104/2	0	01	80
	100	0	05	70
	101	0	17	40

[सं० O-12016/178/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3858.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-397 to G.G.S. V in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from K. 397 to GGS. V

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Wadavswami	100	0	09	00
	107	0	13	50
	106	0	07	50
	104/2	0	01	80
	100	0	05	70
	101	0	17	40

[N. O-12016/178/86—ONG-D 4]

का० आ० 3859 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात

राज्य में कूप नं०-15 से एस०आई०पी०-34 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 15 से एस०आई०पी०-34 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आरे०	सेन्टीयर
हाजीपुर	615/1	0	07	50
	1/ए			

[सं० O-12016/181/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3859.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P. 34 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from Well No. 15 to SIP 34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Hajipur	615/1 1/A	0	07	50

[No. O-12016/181/86-ONG-D 4]

कांसा० 3860.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी०जी०एस० XI से जी०जी०एस० I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवस्था की मार्फत।

अनुसूची

जी०जी०एस० XI से जी०जी०एस० I तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	लाक न०	हवटयर	आर०	सन्टायर
1	2	3	4	5
अडालज	576	0	06	80
	576	0	17	40
	569	0	07	80

1	2	3	4	5
अडालज (जारी)	571	0	02	70
	570	0	11	80
	557	0	03	40
	556	0	09	00
	555	0	01	70

[सं० O-12016/182/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3850.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. XI to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS XI To GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Adalaj	576	0	06	80
	576	0	17	40
	569	0	07	80
	571	0	02	70
	570	0	11	80
	557	0	03	40
	556	0	09	00
	555	0	01	70

[No. O-12016/182/86-ONG-D 4]

कांसा० 3861.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना कां० सां० सं० 1270, तारीख 6-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सभ्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और शायद, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार मजिद करने का विनिश्चय किया है।

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार वाशवाहन विद्याने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा मजिद किया जाना है।

और शायद उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की वजह से और प्राकृतिक गैस शायद में सभी वाशवाहों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

जी०जी०एस०-II से सोहासन सी०टी०एफ० तक पाइपलाइन विद्याने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आरे०	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पुनासन	404/2	0	05	70
	403	0	03	00
	360	0	00	10
	402	0	00	40
	372	0	01	70
	373	0	04	40
	374	0	03	75
	393	0	01	00
	392	0	03	50
कार्ट ट्रैक	0	00	50	
	391	0	02	60
	390	0	04	30
	432	0	02	10
	433	0	01	75
	434	0	02	75
	90	0	01	50
	4	0	02	80
	3	0	02	25
कार्ट ट्रैक	0	00	15	

1	2	3	4	5
पुनासन (आरी)	68	0	05	50
	87	0	01	10
	73	0	00	15
	74	0	02	00
कार्ट ट्रैक	0	00	50	
	86	0	06	00
	80	0	01	00
	82	0	04	50
	81	0	01	50
	0	00	25	

[सं० O-12016/31/85/-मोएनजी-सी-4]

S.O. 3861.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 1270 dated 6-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration, in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS II to C.T.F. Sobhasan

State : Gujarat District & Taluka : Mahsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Punasan	404/2	0	05	70
	403	0	03	00
	360	0	00	10
	402	0	00	40
	372	0	01	70
	373	0	04	40
	374	0	03	75
	393	0	01	00
	392	0	03	50
	Cart track	0	00	50
	391	0	02	60
	390	0	04	30
	432	0	02	10
	433	0	01	75
	434	0	02	75

1	2	3	4	5
Pubasan (Contd.)	90	0	01	53
	4	0	02	60
	3	0	02	25
	Cart track	0	00	15
	68	0	05	50
	87	0	01	10
	73	0	00	15
	74	0	02	00
	Cart track	0	00	50
	86	0	06	00
	80	0	01	00
	82	0	04	50
	81	0	01	50
	Cart track	0	00	25

[No. O-12016/31/85-ONG-D4]

कां० 3862.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वासना-7 से वासना-3 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी शर्तों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अतिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा बहोदरा-9 को इस धिसूचना की तारीख से 21 दि के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

कृ० मं० वासना-7 से वासना-3 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मेहमदाबाद

गाँव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर आर०	सेन्टीयर
1	2	3	4
महीज	1240	0	04 50
	1227	0	10 38

1	2	3	4	5
महीज (जारी)	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1270	0	20	50
	1292	0	18	45
	1295	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[सं० O-12016/179/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3862.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Wasna-7 to Wasna-3 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. Wasna-7 to Wasna-3

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Mehamdabad

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-tare
Mahij	1240	0	04	50
	1227	0	10	35
	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1278	0	20	50
	1292	0	18	45
	1295	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[No. O-12016/179/86-ONG-D 4]

का.आ. 3863:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. के-443 से डब्ल्यू एच आई पानसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं. के-443 से डब्ल्यू एच आई पानसर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात तालुका : कक्कोल जिला : मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	अ.र.	सेंटीयर
पानसर	17	0	08	80
	17	0	09	15
कार्ट ट्रक	0	01	35	
	1637	0	04	50
	1636	0	09	75
	1640	0	07	50
	1610	0	11	10
	1611	0	11	85
	1601	0	09	75
	1602	0	03	30
	1600	0	09	15
	1604	0	05	70
	1600	0	01	50

S.O. 3863.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-443 to WHZ-Pansar in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-443 to WHI Pansar

State : Gujarat Taluka : Kakol District : Mehsana

Village	Block No.	Hecta- are	Are Centi- are
Pansar	17	0	08 80
	17	0	09 15
	Cart Track	0	01 35
	1637	0	04 50
	1636	0	09 75
	1640	0	07 50
	1610	0	11 10
	1611	0	11 85
	1601	0	00 75
	1602	0	03 30
	1600	0	09 15
	1604	0	05 70
	1600	0	01 50

[No. O-12016/190/86-ONG D4]

का.आ. 3864:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. कलाल-8 से के-188 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

[त. O-12016/190/86-ओ एन जी-डी-4]

यशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं. कलोल-8 से के-188 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	सेंटीमीटर
जमीयतपुरा	336	0	03 00
	311	0	07 50
	334	0	02 35
	312	0	06 30
	313	0	09 15
	310	0	09 15
	308	0	21 00
	298	0	09 00
	297	0	06 00
	271	0	07 05
	270	0	09 30
	259	0	06 00
	261	0	06 15
	237	0	16 50
	229	0	10 50
	230	0	13 50
	3	0	12 30
	42	0	26 30
	54	0	12 60

[सं. O-12016/184/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3864.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Kulal-8 to Well No. K-188 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Kalol-8 to K-188
State : Gujarat Taluka & District : Gandhinagar

Village	Block No.	Hect-are	Centi-are
Jamiyat Pura	336	0	03 00
	311	0	07 50
	334	0	02 35
	312	0	06 30
	313	0	09 15
	310	0	09 15
	308	0	21 00
	298	0	09 00
	297	0	06 00
	271	0	07 05
	270	0	09 30
	259	0	06 00
	261	0	06 15
	237	0	16 50
	229	0	10 50
	230	0	13 50
	3	0	12 30
	42	0	26 30
	54	0	12 60

[No. O-12016/184/86-ONG-D-4]

का. आ. 3865:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. के-243 से जी सी एस कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भावद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० के-243 से जी सी एस कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लॉक नं	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
ओला	471	0	06	00
	473	0	06	60
कार्ट ट्रक		0	01	05
	474	0	10	65

[स O-12016/183/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3865.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-243 to G.C.S. Kulal in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-243 to GCS Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hecta- are	Are	Con- tiare
Ola	471	0	06	00
	473	0	06	60
	Cart Track	0	01	05
	474	0	10	65

[No. O-12016/183/86-ONG-D4]

का.आ. 3866:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. 15 से एस आई पी 34 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० 15 से एस आई पी 34 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लॉक नं	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
1	2	3	4	5
जेठलज	372/2	0	06	50
	364/1	0	01	50
	364/2	0	04	70
	362/1	0	03	00
	357/1	0	04	70
	357/2	0	01	45
	कार्ट ट्रक	0	00	45
	475	0	03	45
	477/3	0	01	05
	477/1	0	2	50
	478/बी/1	0	3	53
	478/1/सी	0	2	55
	4 9/1/ए	0	0	50
	480/2	0	1	95
	480/1	0	2	20
	486	0	3	55
	483	0	1	15
	484	0	04	20
	550/2	0	04	50

1	2	3	5	6
	550/1	0	04	35
	1	0	07	20
	7	0	02	20
	8/2	0	00	80
	9/2	0	02	20
	10/પો	0	00	75
	10/પો	0	01	70
	24/1	0	01	00
	27/2	0	01	00
	28	0	01	70
	29/2	0	01	70
	30/1	0	01	80
	31/પો	0	02	10
	31/પો	0	05	90
	32/2	0	03	45
	32/પો	0	01	95
	32/પો	0	02	10
	કાટું ટ્રક	0	02	35
	162/2	0	02	65
	162/1	0	01	65
	148	0	03	85
	149	0	04	20
	146	0	02	15
	98/1	0	04	25
	99/2	0	03	40
	89	0	01	40
	91/2	0	12	30
	92/2	0	04	50
	92/1	0	00	50
	61	0	03	55
	60	0	03	00
	58	0	02	60
	56	0	03	75
	57	0	04	05

[No. O-12016/188/86-ઓનગ્રી ડી-4]

S.O. 3866.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P.-34 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipelining from Well No. 15 to S.I.P. 34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hecta- are	Are	Centi- tare
1	2	3	4	5
Jethlaj	372/2	0	06	50
	364/1	0	01	50
	364/2	0	04	70
	362/1	0	03	00
	357/1	0	04	70
	357/2	0	01	45
	Cart Track	0	00	45
	475	0	03	45
	477/3	0	01	05
	477/1	0	2	50
	478/B/1	0	3	55
	478/1/C	0	2	55
	479/1/A	0	0	50
	480/2	0	1	95
	480/1	0	2	20
	486	0	3	55
	483	0	1	15
	484	0	04	20
	550/2	0	04	50
	550/1	0	04	35
	1	0	07	20
	7	0	02	20
	8/2	0	00	80
	9/2	0	02	20
	10/P	0	00	75
	10/P	0	01	70
	24/1	0	01	00
	27/2	0	01	00
	28	0	01	70
	29/2	0	01	70
	30/1	0	01	80
	31/P	0	02	10
	31/P	0	05	90
	32/2	0	03	45
	32/P	0	01	95
	32/P	0	02	10
	Cart Track	0	00	35
	162/2	0	02	65
	162/2	0	01	65
	148	0	03	85
	149	0	04	20
	146	0	02	15
	98/1	0	04	25
	99/2	0	03	40
	89	0	01	40
	91/2	0	12	30
	92/2	0	04	50
	92/1	0	00	50
	61	0	03	55
	60	0	03	00
	58	0	02	60
	56	0	03	75
	57	0	04	05

[No. O-12016/188/86-ONG-D4]

का. प्रा. 3867 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में क-386 1 जी जी एस 6 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुमोचनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के - 386 से जी. जी. एस - 6

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका :- काडी

गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
झुलासन	383	0	14	10
	397/1	0	09	15
	426	0	21	30
	422/1	0	07	50
	421	0	06	00
	420	0	06	00
	430	0	06	75
	431/1	0	17	10
	434	0	14	70

[सं O-12016/187/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3867.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-386 to G.G.S.-6 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe Line from K-386 to GGS 6.

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Zulasan	383	9	14	10
	397/1	0	09	15
	426	0	21	30
	422/1	0	07	50
	421	0	06	00
	420	0	06	00
	430	0	06	75
	431/1	0	17	10
	434	0	14	70

[No. O-12016/187/86-ONG-D 4]

का.प्रा. 3868 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 3208 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है;

और आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

गांव - वाघोली तहसील-हवेली जिला-पुणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वाघोली	2063	"	00-40
	2060	"	00-11
	2062	"	00-24
	2069	"	00-20
	2070	"	00-01
	2074	"	00-06
	2075	"	00-11
	2076	"	00-11
	2077	"	00-11
	2078	"	00-33
	2079	"	00-22
	2089	"	00-09
	2222	"	00-21
	2223	"	00-18
	2225	"	00-27
	2226	"	00-18
	2229	"	00-09
	2230	"	00-04
	2272	"	00-27
	2273	"	00-61
	2274	"	00-38
	2275	"	00-25
	2272	"	00-76
	2307	"	00-67
	2328	"	00-33
	2329	"	00-76
	2333	"	00-47
	2335	"	00-34

[सं 0-12016/57/83-प्रोड]

S.O. 3868.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 3208 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Village : Magholi Tahsil : Haveli, Dist : Pune

Village	Survey No.	Gut No.	Hissa No.	Area H A
Vagholi	2063	Part		00 40
"	2060	"		00 11
"	2062	"		00 24
"	2069	"		00 20
"	2070	"		00 01
"	2074	"		00 06
"	2075	"		00 11
"	2076	"		00 11
"	2077	"		00 11
"	2078	"		00 33
"	2077	"		00 22
"	2089	"		00 09
"	2222	"		00 21
"	2223	"		00 18
"	2225	"		00 27
"	2226	"		00 18
"	2229	"		00 09
"	2230	"		00 04
"	2272	"		00 27
"	2273	"		00 61
"	2274	"		00 38
"	2275	"		00 25
"	2272	"		00 76
"	2307	"		00 67
"	2328	"		00 33
"	2329	"		00 76
"	2333	"		00 47
"	2335	"		00 34

[No. O&I2016/57/83-Prod]

का. आ. 3869 :—यतः पेट्रोलियम और जनिज पाईप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) को धारा 3 को उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3196 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अधिनियम करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और आगे सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बंबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तहसील - खेड जिला - पुणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
सांगुंडे	76	"	00-03-60
	111	"	00-10-08
	112	"	00-07-92
	129	"	00-30-24

[सं. O-12016/142/86 - ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3869.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 3196 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government ;

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Village : Sangunde Tehsil : Khed Dist : Pune, Maharashtra

Village	S. No.	H. No.	Area
Sangunde	76	Part	00 03 60
	111	"	00 10 08
	112	"	00 07 92
	129	"	00 30 24

[No. O-12016/142/86-ONG-D4]

का. भा. 3870.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3196 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तहसील - खालापुर जिला - रायगड, महाराष्ट्र

सं०	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
(1)	लोधीवली	106	—	00-01-35
		107-अ	—	00-05-40
		108	7	00-04-75

1	2	3	4	5
(2)	मसरोली	41	1	00-04-50
		53	—	00-01-50
(3)	निगडोली	39	—	00-25-38
		89	1	00-08-82
		89	2	00-02-25
		97	4(1)	00-08-75
		97	4	00-06-12
		97	5	00-16-64
		100	5	00-06-94
		100	6	00-10-08
		100	9	00-07-74
		106	—	00-23-92
		119	—	00-23-00
(4)	शिरवली	7	—	00-07-70
		13	—	00-02-70
(5)	कस्बे खालापुर गांवठाण का भाग			00-10-35
		131	1	00-12-78
(6)	मध	72	4	00-09-65
		101	—	00-03-60
		103	—	00-03-24
		104	1	00-00-90
(7)	हालखुर्द	27	—	00-04-05
(8)	अजोशी	6	1	00-16-00
		13	—	00-04-00
(9)	शेल	19	2	00-03-00
		2452		00-01-86
		2450		00-01-68
	सीटीएस 2443 का भाग			00-03-38
(10)	वरोसे	16	का भाग	00-06-37
(11)	काटरंग	3	"	00-12-15

[सं O-12016/143/86 - ओ एन जी-डी - 4]

S.O. 3870.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 3195 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government,

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines,

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from Lodhivali to Katrang.

Taluka : Khalapur. Dist : Raigad, Maharashtra.

Sr. Village No.	S. No. G. No.	H. No.	Area
1. Lodhivali.	105 (pt)	..	00 01 35
	107-A	..	00 05 40
	108	7	00 04 75
2. Asroli.	41	1	00 04 50
	53 (pt)	..	00 01 50
3. Nigdoli.	39 (pt)	..	00 25 38
	89	1A	00 08 82
	89	2B	00 02 25
	97	4A(1)	00 08 75
	97	4K	00 06 12
	97	5	00 16 64
	100	5	00 06 94
	100	6	00 10 08
	100	9	00 07 74
	106 (pt)	..	00 23 92
	119 (pt)	..	00 23 00
4. Shirvali	7 (pt)	..	00 07 70
	13 (pt)	..	00 02 70
5. Karbe Khalapur.	Gaothan	(Part)	00 10 35
	131	1	00 12 78
6. Madh.	72	4	00 09 65
	101 (pt)	..	00 03 60
	103 (pt)	..	00 03 24
	104	1	00 00 90
7. Hal. Rd.	27 (pt)	..	00 04 05
8. Ajoshi	6	1	00 16 00
	13 (pt)	..	00 04 00
9. Sheel.	19	2	00 03 00
	C.T.S.	2452 (pt)	00 01 86
	C.T.S.	2450 (pt)	00 01 68
	C.T.S.	2443 (pt)	00 03 38
10. Varose.	16	(pt)	00 06 37
11. Katrang.	3	(pt)	00 12 15

[No. O-12016/143/86-ONG-D4]

ई. दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

शुद्धि पत्र

का. आ. 3871:—भारत सरकार के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड, (ii) दिनांक 16/4/1983 पृष्ठ क्रमांक 1831, 1832, और 1833 का. आ. संख्या 12016/31/82-प्रोड-II के अंतर्गत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 1861 दिनांक 16-4-1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा, (i) के अधीन वर्णित गांव-1 निगडोली 2. शिखली 3. वणवे 4. निबोडे 5. तडोये तहसील खालापूर जिला-रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में भूमि में खसरा नं., हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि की धारा 56 के उपधारा (i) के अधिसूचना के अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

कालम 2 पढ़ें—

भाग I

कालम 1 के लिये

गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल है.	गांव आ. से.	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल है. आ. से.
निगडोली	59	0	00-11-40	निगडोली	59	का भाग	00-06-00
"	60	0	00-01-35	"	60	"	00-06-00
"	61	0	00-14-00	"	61	"	00-07-00
"	62	1	00-07-75	"	62	"	00-07-00
"	63	0	00-18-30	"	63	"	00-22-00
"	64	1	00-07-50}	"	64	"	00-13-00
"	64	17-ब	00-11-88]	"			
"	83	0	00-41-59	"	83	"	00-73-00
"	84	0	00-07-00	"	84	"	00-07-00
"	85	1	00-06-12	"	85	"	00-22-00
"	90	0	00-00-56	"	90	"	00-18-00
"	111	0	00-18-90	"	111	"	00-15-00
"	113	2 क	00-03-00	"	113	"	00-22-00
"	114	0	00-14-12	"	114	"	00-11-00
"	118	3	00-14-38	"	118	"	00-38-00
"	118	4 अ	00-12-12				
"	118	12 अ	00-18-00				
"	120	5 अ	00-05-40	"	120	"	00-23-00
"	120	5 ब	00-06-00				
"	120	5 क	00-08-10				
"	120	5 ड	00-04-32				

भाग - II

निगडोली	91	का भाग	00-07-00
"	92	"	00-13-00
"	95	"	00-09-00
"	96	"	00-12-00
"	107	"	00-37-00

अनुसूची

कालम 2 पढ़ें

भाग I

कालम 1 के लिए

गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. आ. से.	गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. आ. से.
शिरबली	4	1	00-10-26	शिरबली	4	का भाग	00-15-00
"	4	2	00-05-40	"	"	"	"
"	5	0	00-07-84	"	5	"	00-15-00
"	10	0	00-06-57	"	10	"	00-07-00
"	11	0	00-05-40	"	11	"	00-02-00
"	12	0	00-05-40	"	12	"	00-07-00
"	34	1	00-04-40	"	34	"	00-07-00
"	35	1	00-03-60	"	35	"	00-04-00
"	35	2	00-02-70				
"	35	3	00-03-15				
"	35	4	00-02-70				
"	42	0	00-05-15	"	42	"	00-02-00
"	43	0	00-20-25	"	43	"	00-18-00
"	55	0	00-03-24	"	55	"	00-10-00
"	56	0	00-06-48	"	56	"	00-04-00
"	57	0	00-18-00	"	57	"	00-13-00
"	60	2	00-25-10	"	60	"	00-22-00

भाग II

शिरबली	6	का भाग	00-01-00
"	51	"	00-04-00
"	41	"	00-11-00
"	54	"	00-01-00

अनुसूची

कालम 2 पढ़ें

भाग I

कालम 1 के लिये

गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. आ. से.	गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. आ. से.
बनवे	1	का भाग	00-02-70	बनवे	1	का भाग	00-19-00
	2	1	00-08-00		2		00-11-00
	3	का भाग	00-05-40		3		00-09-00
	4		00-08-10		4		00-04-00
	14		00-21-15		14		00-26-00
	15		00-16-06		15		00-07-00
	27	1	00-16-08		27		00-18-00
	27	2	00-04-77				
	32	का भाग	00-08-64		32		00-07-00
	47		00-09-18		47		00-04-00
	48		00-09-46		48		00-09-00
	50		00-02-40		50		00-05-00
	51		00-08-66		51		00-16-00
	52		00-08-26		52		00-05-00

भाग II

बनवे	46	का भाग	00-04-00				
भाग I							
निबोडे	30	1	00-01-98	निबोडे	30	का भाग	00-02-00
	34	7	00-06-30		34		00-14-00
	36	0	00-03-75		36		00-20-00
	37	3	00-02-70		37		00-23-00
	41	2क	00-28-08		41		00-30-00
	41	का भाग	00-16-72				
	56	1	00-10-80		56		00-22-00
	56	2	00-15-75				
	56	3	00-17-28				
	58	का भाग	00-06-48		58		07-00
	59	1	00-01-35		59		00-10-00
अनुसूची							
भाग 1				कालम 1 के लिये			
गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. घ्रा. से.	गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे. घ्रा. से.
निबोडे	62	3	00-12-65	निबोडे	62	(Pt)	00-27-00
	62	5बी + 8	00-22-86				
	62	5	00-07-77				
	63	1	00-04-25		63	(pt)	00-16-00
	63	2	00-04-50				
भाग 2							
निबोडे	64	का भाग	00-14-00				
भाग 1							
नडोथे	26	का भाग	00-34-40	नडोथे	26	का भाग	00-14-00
	28		00-60-00		28		00-23-00
	43	1	00-17-42		43		00-57-00
	43	4	00-10-80				
	43	15	00-03-00				
	43	16	00-18-00				
	43	19	00-06-00				
	43	23	00-08-82				
	48	5ए	00-29-70		48		00-18-00
	54	का भाग	00-12-00		54		00-06-00
	69		00-06-75		69		00-23-00
	70		00-18-90		70		00-05-00
	74	1	00-03-37		74		00-18-00
	74	2	00-05-94				
	74	3	00-05-85				
	75	का भाग	00-06-07		75		00-09-00
	79	भाग II	00-33-12		79		00-32-00
नडोथे	68	का भाग	00-05-00				
	78		00-37-00				

ह./-सक्षम प्राधिकारी

[सं. O-12018/31/82-प्रोड 1]

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3871.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No-12016/31/82/Prod-II dated 16th April, 1983 published under S.O. No. 1861 in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (ii) at pages 1831, 1832 & 1833 issued under Section 6 of sub-section (i) of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 in respect of villages : 1. Nigdoli 2. Shirwali 3. Vanve 4. Nimbode

5. Nadodhe Tahasil Khalapur. District Raigad, State Maharashtra, for S. Nos., Hissa Nos. and areas shown in the Column No-1 of the schedule appended to this corrigendum, read the S. Nos, H. Nos, and areas as shown in the column No II of the said schedule.

2. Lands mentioned in the part II of the appended schedule, however, do not come under the pipe line project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 sub-section (i) referred to above.

Read (Col.II)

SCHEDULE

For (Col. I)

PART-I

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.	Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.
Nigadoli	59	(pt)	00-11-40	Nigadoli	59	(pt)	00-06-00
	60	(pt)	00-01-35		60	(pt)	00-06-00
	61	(pt)	00-14-00		61	(pt)	00-07-00
	62-1	(pt)	00-07-75		62	(pt)	00-07-90
	63	(pt)	00-18-30		63	(pt)	00-22-00
	64-1	(pt)	00-07-50		64	(pt)	00-13-00
	64	17/B	00-11-88		83	(pt)	00-73-00
	83	(pt)	00-41-59		84	(pt)	00-07-00
	84	(pt)	00-07-00		85	(pt)	00-22-00
	85	1	00-06-12		90	(pt)	00-18-00
	90	(pt)	00-00-56		111	(pt)	00-15-00
	111	(pt)	00-18-90		113	(pt)	00-22-00
	113	2 K	00-03-00		114	(pt)	00-11-00
	114	(pt)	00-14-12		118	(pt)	00-38-00
	118	3	00-14-38				
	118	4A	00-12-12		120	(pt)	00-23-00
	118	12A	00-18-00				
	120	5A	00-05-40				
	120	5B	00-06-00				
	120	5K	00-08-10				
	120	5D	00-04-32				

PART-II

Nigdoli	91	(pt)	00-07-00
	92	(pt)	00-13-00
	95	(pt)	00-09-00
	96	(pt)	00-12-00
	107	(pt)	00-37-00

SCHEDULE

Read Col.-II

For Col.-I

Part I

Village	S.No. G.No.	H. No.	Area H.R.C.	Village	S.No. G.No.	H. No.	Area H.R.C.
Shirwali	4	1	00-10-26	Shirwali	4	(pt)	00-15-00
	4	2	00-05-40		5	(pt)	00-15-00
	5	(pt)	00-07-84		10	(pt)	00-07-00
	10	(pt)	00-06-57		11	(pt)	00-02-00
	11	(pt)	00-05-40		12	(pt)	00-07-00
	12	(pt)	00-05-40		34	(pt)	00-07-00
	34	1	00-04-40				
	35	1	00-03-50		35	(pt)	00-04-00
	35	2	00-02-70		42	(pt)	00-02-00
	35	3	00-03-15		43	(pt)	00-18-00
	35	4	00-02-70		55	(pt)	00-10-00
	42	(pt)	00-05-15		56	(pt)	00-04-00
	43	(pt)	00-20-25		57	(pt)	00-13-00
	55	(pt)	00-03-24		60	(pt)	00-22-00
	56	(pt)	00-06-48				
	57	(pt)	00-18-00				
	60	2	00-25-10				

PART-II

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.
Shirvali	6	(pt)	00-01-00
	51	(pt)	00-04-00
	41	(pt)	00-11-00
	54	(pt)	00-01-00

SCHEDULE

Read (Col II)

For (Col I)

PART-I

Village	S. No. G.No.	H. No.	Area H.R.C.	Village	S.No. G.No.	H. No.	Area H.R.C.
Wanave	1	(pt)	00-02-70	Wanave	1	(pt)	00-19-00
	2	1	00-08-00		2	(pt)	00-11-00
	3	(pt)	00-05-04		3	(pt)	00-09-00
	4	(pt)	00-08-10		4	(pt)	00-04-00
	14	(pt)	00-21-15		14	(pt)	00-25-00
	15	(pt)	00-16-06		15	(pt)	00-07-00
	27	1	00-16-08		27	(pt)	00-18-00
	27	2	00-04-77				
	32	(pt)	00-08-64		32	(pt)	00-07-00
	47	(pt)	00-09-18		47	(pt)	00-04-00
	48	(pt)	00-08-46		48	(pt)	00-09-00
	50	(pt)	00-02-40		50	(pt)	00-05-00
	51	(pt)	00-08-66		51	(pt)	00-16-00
	52	(pt)	00-08-26		52	(pt)	00-05-70

PART-II

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.	Village	S.No. G.No.	H. No.	Area H.R.C.
Nimbode	30	1	00-01-78	Nimbode	30	(pt)	00-02-00
	34	7	00-06-30		34	(pt)	00-14-00
	36	0	00-03-75		36	(pt)	00-20-00
	37	3	00-02-00		37	(pt)	00-23-00
	41	2K	00-28-08		41	(pt)	00-30-00
	41	(pt)	00-18-72				
	56	1	00-10-80		56	(pt)	00-22-00
	56	2	00-15-75				
	56	3	00-17-28				
	58	(pt)	00-06-48		58	(pt)	07-00-00
	59	1	00-01-35		59	(pt)	00-10-00

SCHEDULE

Read Col II

For Col-I

PART-II

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.	Village	S.No. G.No.	H.No.	Area H.R.C.
Nimbode	62	2	00-12-65		62	(pt)	00-27-00
	62	5 B + 8	00-22-86				
	62	5	00-07-77				
	63	1	00-04-25				
	63	2	00-04-50				

PART-II

Village		S.No.	H.No.	Area			
Nimbode		64	(pt)	00-14-00			
PART-I							
Nadodhe	26	(pt)	00-34-40	Nadodhe	26	(pt)	00-14-00
	28	(pt)	00-60-90		28	(pt)	00-23-00
	43	1	00-17-42		43	(pt)	00-57-00
	43	4	00-10-80				
	43	15	00-03-00				
	43	16	00-18-00				
	43	19	00-06-00				
	43	23	00-08-82				
	48	5A	00-29-70		48	(pt)	00-18-00
	54	(pt)	00-10-26		54	(pt)	00-06-00
	69	(pt)	00-06-75		69	(pt)	00-23-00
	70	(pt)	00-18-00		70	(pt)	00-05-00
	74	1	00-03-37		74	(pt)	00-18-00
	74	2	00-05-94				
	74	3	00-05-85				
	75	(pt)	00-06-07		75	(pt)	00-09-00
	77	(pt)	00-33-12		79	(pt)	00-32-00

PART-II

Village	S. No. G.No.	H. No.	Area
			H.R.C.
Nadodhe	68	(pt)	00-05-00
	78	(pt)	00-37-00

Sd/- Competent Authority
[No. O-12016/31/82-Prod. I]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

शुद्धिपत्र

का. घा. 3872—भारत सरकार के राजपत्र विभाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 20-9-1986 का भा. संख्या O-12016/31/82-प्रोड-II की अधिसूचना संख्या 3201 दिनांक 20-9-1986 पृष्ठ क्रमांक 3636 से 3640 तक जोड़े हुए अनुसूची में नीचे वर्णित किया हुआ बदल किया जाता है।

1 गांव निबोदे

के लिए

पड़े

खसरा नं० हि. नं० क्षेत्रफल

खसरा नं० हि. नं० क्षेत्रफल

(i) 62-9-00-07-77

62-5-00-07-77

(ii) गांव नडोदे

के लिये

पड़े

खसरा नं० हि. नं० क्षेत्रफल

खसरा नं० हि. नं० क्षेत्रफल

(i) 54 का भाग 00-12-06

54-का भाग 00-10-26

ह०/- सक्षम अधिकारी

[नं० O-12016/31/82-प्रोड]

पी. के. राजगोपालन, डेस्क ऑफिसर

New Delhi, the 29th October, 1986

ERRATUM

S. O. 3872.—For the words and figures appearing in the Corrigendum to section 3 (i) Notification issued under Govt. of India's Notification No. O-12016/31/82-Prod-II under S.O. 3201 dated 20th September 1986 (Published in Govt. of India Gazette Part II—Section 3 (ii) page No. 3640 dated 20-9-86, read.

(i) Village—Nimbodhe

(i) S.No.	For		Road		
	H. No.	Area	S.No.	H.No.	Area
62	9	00-07-77	62	5	00-07-77

(ii) Village—Nadodhe

(i) S.No.	H.No.	Area	S.No.	H.No.	Area
54	(pt)	00-12-06	54	(pt)	00-10-26

Sd/-

Competent Authority,

[No. O-12016/31/82-Prod]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का. घा. 3873.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में राज्य सभा ने अपने सदस्यों में से श्रीमती विजय चक्रवर्ती को 13 मई, 1986 से श्रीमती रोडा मिस्त्री के स्थान पर भारतीय उपचर्या परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3(i)

तारीख 6 दिसम्बर, 1958 में वृष्ट संख्या 1131 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.सा. 1147 तारीख पहली दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत प्रथम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"3. श्रीमती बिजय चक्रवर्ती, संसद सदस्य"

[संख्या बी. 14013/1/86-पी.एम.एस.]

शोभना राजेन्द्रन, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deptt of Health)

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3873.—Whereas in pursuance of clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Rajya Sabha has elected from among its Members Shrimati Bijoy Chakravorty on the 13th May, 1986 to be a Member of the Indian Nursing Council in place of Shrimati Roda Mistry.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health No. S.O. 1147, dated the 1st December, 1958, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 6th December, 1958, at page 1131, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (o) of sub-section (1) of section 3", for serial number 3 and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be substituted, namely :—

"3. Shrimati Bijoy Chakravorty, Member of Parliament."

[No. V. 14013/1/86-PMS]

SHOBHANA RAJENDRAN, Dy. Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलूर, 20 अक्टूबर, 1986

का. सा. 3874 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 में :—

(i) "खंड VIII—पुनरीक्षण" शीर्षक के लिए निम्न-

लिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"खंड VIII—परिशोधन और पुनरीक्षण", और "पुनरीक्षण" हाशिये शीर्षक के लिए "परिशोधन" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 26 के उप-नियम (1) में

(क) "पुनरीक्षण" शब्द के लिए "परिशोधित" शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा और "पुनरीक्षण किया गया" शब्द के लिए "परिशोधित किया गया" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) पहले परन्तुक में, "पुनरीक्षण प्राधिकारी" शब्द के लिए "परिशोधन प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा और "पुनरीक्षण किया गया" शब्द के लिए "परिशोधित किया गया" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) दूसरे परन्तुक में, "पुनरीक्षण के अधिकार" शब्दों के लिए "परिशोधन के अधिकार" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) नियम 26 के उप-नियम (2) में, "पुनरीक्षण" शब्द के लिए "परिशोधन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iv) नियम 26 के उप नियम (3) में, "पुनरीक्षण" शब्द के लिए "परिशोधन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(v) नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

"26-अ पुनरीक्षण—राष्ट्रपति, किसी भी समय स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, इन नियमों के अंतर्गत पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा, जब कोई साक्ष्य या नई चीजें जो पुनरीक्षण के अधीन आदेश पारित करने समय प्रस्तुत नहीं कर पाए या उपलब्ध नहीं करा सकें और जिसमें मामले की प्रकृति को ही बदलने के विचार उसके ध्यान में आयें या लाया जाए।

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा शास्ति अधिरोपित या वद्धित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 8 में विनिर्दिष्ट प्रमुख शास्तियों में से कोई शास्ति या उस आदेश द्वारा अधिरोपित लघु शास्ति को कोई प्रमुख शास्ति के रूप में वद्धित करने के लिए पुनरीक्षण चाहा गया हो और यदि पहले ही मामले में नियम 11 के अधीन जांच नहीं किया गया हो, और जब तक नियम 16 के प्रावधानों के शर्त पर नियम 11 में निर्धारित रीति से जांच किए बिना, तथा जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक

हो, वहाँ ऐसे परामर्श किए बिना ऐसी शास्ति, अधिरोपित नहीं की जायगी।”

[सं० 2/5(2)/86-V]

टी० एस० वेंकटरामन, उप सचिव

टिप्पण : प्रधान नियमों को दिनांक 1-4-1976 के अधिसूचना सं 2/9(12)/74-III(I) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 1-4-1976 को प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् निम्नप्रकार संशोधन किये गये :—

क्रम सं	अधिसूचना सं	दिनांक
1.	2/10(32)/76-I	10-02-1977
2.	2/10(32)/76-I	16-05-1977
3.	2/10(27)/76-I	01-08-1977
4.	2/7(5)/77-I	15-02-1978
5.	2/7(5)/77-I	27-05-1978
6.	2/9(12)/74-III(I)	16-03-1979
7.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
8.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
9.	9/4(1)/80-III	05-09-1980
10.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
11.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
12.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
13.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
14.	2/8(1)/81-I	28-08-1981
15.	2/8(1)/81-I	16-07-1982
16.	2/9(1)/83-I(V)	29-07-1985
17.	2/5(1)/85-V	02-01-1986
18.	2/9(1)/83-I(V)	02-01-1986
19.	2/5(1)/86-V	17-03-1986

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 20th October, 1986

S.O. 3874.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 :—
 - (i) for heading “Part VIII—Review”, the following heading shall be substituted namely :—

“Part VIII—Revision and Review”, and for the marginal heading “Review”, “Revision” shall be substituted.”
 - (ii) in sub-rule (1) of Rule 2b
 - (a) for the word ‘review’, the word ‘revise’ shall be substituted and for the word ‘reviewed’ the word ‘revised’ shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words ‘reviewing authority’, the words ‘revising authority’ shall be substituted and for the word ‘reviewed’ the word ‘revised’ shall be substituted;

(c) in the second proviso, for the words “power of review”, the words “power of revision” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) of rule 26, for the word ‘review’ the word ‘revision’ shall be substituted;

(iv) in sub-rule (3) of the rule 26 for the word ‘review’, the word ‘revision’ shall be substituted;

(v) after rule 26, the following rule shall be inserted namely :—

“26-A Review—The President may, at any time, either on his own motion or otherwise, review any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 11, subject to the provisions of rule 16, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary.”

[No. 2/5(2)/86-V]

T. S. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

NOTE : Principal rules were published vide Notification No. 2/9(12)/74-III(I) dated 1-4-1976 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 1-4-1976 and have been subsequently amended by :—

Sl. No.	Notification No.	dated
1.	2/10(32)/I76-I	10-02-1977
2.	2/10(32)/76-I	16-05-1977
3.	2/10(27)/76-I	01-08-1977
4.	2/10(5)/77-I	27-05-1978
5.	2/7(5)/77-I	27-05-1978
6.	2/9(12)/74-III(I)	16-03-1979
7.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
8.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
9.	9/4(1)/80-III	05-09-1980
10.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
11.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
12.	9/4(1)/80-III	20-12-1970
13.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
14.	2/8(1)/81-I	28-08-1981
15.	2/8(1)/81-I	16-07-1982
16.	2/9(1)/83-I(V)	29-07-1985
17.	2/5(1)/85-V	02-01-1986
18.	2/9(1)/83-I(V)	02-01-19786
19.	2/5(1)/86-V	17-03-1986

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

आदेश

का.आ. 3875.—आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के आदेश संख्या एफ. 8-5/80, पी.एन.-1 दिनांक 14 नवम्बर, 1980, सं. एफ. 43-24/82-आई.एन.सी. (यू.यू.) (ए.यू.आर.) दिनांक 18 मई, 1983, सं. एफ. 43/24/82-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.) दिनांक 3 नवम्बर, 1983 तथा सं. एफ. 43-24/82-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.)/यू.यू. दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के आदेश सं.एफ. 43-24/82-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.) दिनांक 24 जनवरी, 1986 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल.पी. निगम की उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्ति की अधि 9 नवम्बर, 1987 तक बढ़ाती है।

[सं.एफ. 43-24/82-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.)]

बलदेव महाजन, निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 7th November, 1986

ORDER

S.O. 3875.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 of the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980 (59 of 1980) and in continuation of the orders of the Central Government in the Ministry of Education and Culture (Department of Education) No. F. 8-5/80-PN-1, dated the 14th November, 1980, No. F. 43-24/82-INC(UU)(AUR), dated the 18th May, 1983, No. F. 43-24/82-INC(AUR)UU, dated the 3rd November, 1983, No. F. 43-24/82-INC(AUR)UU, dated the 31st October, 1984 and the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Order No. F. 43-24/82-INC(AUR)UU, dated the 24th January, 1986, the Central Government hereby extends the term of appointment of Justice L. P. Nigam, retired Judge of the Allahabad High Court as the Administrator for the purpose of the said Act up to the 9th November, 1987.

[No. F. 43-24/82-INC(AUR)UU]

BAI DEV MAHAJAN, Director

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1986

का.आ. 3876.—बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) के खण्ड 7 के उप खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री रमेश चन्द्र, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा की वित्त सलाहकार, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अधि 30 जून, 1986 से 31-7-86 तक की और अधि के लिये एतद्वारा बढ़ाती है।

[सं. 10/47/85-परि. नीज]

के.के. टण्डन, अधीक्षक

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd November, 1986

S.O. 3876.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976), the Central Government hereby further extends the period of deputation of Shri Ramesh Chandra, JA&AS as Financial Adviser, Betwa River Board, Ihansi for a further period with effect from 30th June, 1986 upto 31-7-86.

[No. 10/47/85-P. III]

K. K. TANDON, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3877.—यतः केन्द्रीय सरकार का नीचे लिख क्षेत्रों के बारे में दिल्ली की बृहत योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 19-9-86 को नोटिस संख्या एफ-20(6)/84-एम पी, के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव मांगे गए थे।

और यतः उक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन :—“जीन-डी-3 के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2648.18 वर्ग गज क्षेत्रफल का भूमि उपयोग” सरकारी और अधिसरकारी सुविधाओं “(घोबी घाट और विद्युत सब-स्टेशन स्थल) और “परिचालन” से “सरकारी उपयोग” (वकीलों का चैम्बर) में बदला जाता है, जो उत्तर की ओर शैक्षणिक संस्था (विधि संस्थान), दक्षिण और पूर्व की ओर रिहायशी (सरकारी वंगले) और पश्चिम की ओर सार्वजनिक उपयोगिता (विद्युत सब-स्टेशन) से घिरा है।”

[सं. के-13011/18/84-डी डी-IIए]

एच. के. घोष, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3877.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan

for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(6)/84-MP dated 19-9-86 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, Namely :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 2648.18 sq. yds. falling in Zone D-3 and bounded by Educational Institution (Law Institute) towards its North, residential (Government Bungalows) towards South and East and Public utility (Electric Sub Station) towards West is changed from 'Public and Semi Public facilities (Dhobi Ghat and Electric Sub Station Sites) and Circulation 'to' Governmental use' (Lawyers' Chamber)."

[No. K-13011/18/84-DDHA]

H. K. GHOSH, Desk Officer

(निर्माण प्रभाग—निर्माण-3)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 1986

का.प्रा. 3878. —यतः राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में, श्री आर.के. नारायण, संसद सदस्य को श्री खुशवंत सिंह, संसद सदस्य के स्थान पर राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतत्त्व निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 25 जून, 1985 के का.प्रा. सं. 3793 में जारी अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 10 पर प्रविष्टि "श्री खुशवंत सिंह" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"श्री आर.के. नारायण, संसद सदस्य,"

[फाइल सं. 25011/7/85—निर्माण-3]

डी. एन. भार्गव, निदेशक (इल्यूमीनी.)

(Works Division—W.3)

New Delhi, the 30th October, 1986

S.O. 3878.—Whereas in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), Shri R. K. Narayan, Member of Parliament, has been elected as Member of the Rajghat Samadhi Committee vice Shri Kushwant Singh, Member of Parliament, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Works and Housing number S.O. 3793 dated the 25th June, 1985 namely :

"In the said notification, against serial No. 10, for the entry "Shri Kushwant Singh", the following shall be substituted, namely :—

"Shri R. K. Narayan, M.P."

[F. No. 25011/7/85-W.3]

D. N. BHARGAVA, Director (WP)

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1986

का.प्रा. 3879 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदवर्ती) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 17 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतत्त्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एबी-24023/2/85-एए (एफ. 2) तारीख 23 जुलाई, 1985 को अधिकांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिनियमित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1. उप कलक्टर, (अधिक्रमण) कुर्ली-II टोपी वाला कालेज, मुंबई, मुम्बई।	निम्नलिखित स्थानों में केन्द्रीय सरकार की भूमि— वाई 'केई' तालुक अन्धेरी और कुर्ली
2. उप कलक्टर, (अधिक्रमण) कुर्ली-3 भवन सं. 6 सिंधी कैम्प के निकट नवजीवन सोसाइटी चेम्बर, मुम्बई।	वाई 'एच' तालुक कुर्ली
3. उप कलक्टर (अधिक्रमण), वाई 'एच ई' तालुक अन्धेरी बाँदा एल एच भवन मुम्बई।	वाई 'एच ई' तालुक अन्धेरी

[सं. एबी-24023/2/84-एए (फा. 2)]

ए.एम. सहाय, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 23rd October, 1986

S.O. 3879.—In exercise of the powers conferred section 3 read with section 17 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971) and in pursuance of the notification of the Government of India in the then Ministry of Tourism and Civil—Aviation No. AV. 24023/2/84-AA (F. II), dated the 23rd July, 1985, the Central Government hereby appoints the officers of the Government of Maharashtra mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, who shall

exercises the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table:—

Table	
Designation of Officers (1)	Local limits of jurisdiction (2)
	Land belonging to the Central Government in—
1. Deputy Collector, (Encroachments), Kurla—II, Tapiwala College, Mulund, Bombay.	WARD 'KE', TALUKA ANDHERI AND KURLA
2. Deputy Collector, (Encroachments), Kurla—III, Building No. 6, Sindhi Camp near Nav Jeevan society, Chembur, Bombay.	WARD 'L', TALUKA KURLA
3. Deputy Collector, (Encroachments), Andheri Bandra, MH Building, Bombay.	WARD 'HE', TALUKA AND HERI
[No. AV.24/023/2/84—AA (F. II)] A.M. SEHGAL, Financial Controller.	

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

का. आ. 3880 :—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, उदयपुर को जहाँ के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[सं० हिन्दी-86/रा०भा० 1/12/3]

ए० एन० वांघ, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3880.—In pursuance of Sub-Rule (2) & (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways, Railway Board hereby notify the Zonal Training School, Udaipur of Western Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-86/OL-I/12/3]

A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board & Ex-Officio
Joint Secretary to the Govt. of India.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3881 :—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने वल्लम, कुरुगलम, नाडू कावेरी, मेलाथिरुपन्थुरुथी तथा कल्लापेरम्बूर टेलीफोन केन्द्र तमिलनाडू सर्किल, में दिनांक 16-11-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-26/86-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3881.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 16-11-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vallam, Kurungulam, Naducauvery, Melathirupanthuruthi and Kallaperambur Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-26/86-PHB]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3882 :—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम, 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने एम पुदुपट्टी, थाईलपट्टी, कक्किवाडम्पट्टी, नांगुनेरि, कलककडु, मूल करैपट्टी तथा पाणांकुल टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू सर्किल, में दिनांक 16-11-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-33/86-पी एच बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक, (पी एच बी)

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3882.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 16-11-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in M. Pudupatti, Thayilpatti, Kakkivadamatti, Nanguneri, Kalakad, Moolakaraipatti and Panankulam. Telephone Exchanges, Tamil Nadu Telecom. Circle

[No. 5-33/86-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

आ. 3883:—जबकि भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 (iii) (2सी) के अनुसार कर्वी चित्रकूट टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के लिए कर्वी चित्रकूट में परिचालित समाचार पत्रों में एक सरकारी नोटिस प्रकाशित कराया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ और सुझाव माँगे गए थे;

और जबकि यह नोटिस 15-3-86 को नार्दन इण्डिया पत्रिका और दैनिक जागरण में तथा 17-3-86 को दैनिक कर्मयुग प्रकाश में प्रकाशित कराके तथा 29-7-86 को नार्दन इण्डिया पत्रिका में और 30-7-86 को दैनिक जागरण समाचार पत्रों में संशोधन प्रकाशित कराके जनता के ध्यान में लाया गया था ;

और जबकि जनता से उपर्युक्त नोटिस के बारे में कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

इसलिए, अब उक्त नियमावली के नियम 439 (iii) (2 सी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, दूरसंचार विभाग एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि 16-11-1986 से कर्वी चित्रकूट का स्थानीय क्षेत्र निम्नानुसार होगा ;

कर्वी चित्रकूट टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

कर्वी चित्रकूट टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में चित्रकूट घाम कर्वी नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र शामिल होगा;

यह कि चित्रकूट घाम कर्वी नगरपालिका सीमा से बाहर के टेलीफोन उपभोक्ता जिन्हें कर्वी चित्रकूट टेलीफोन प्रणाली से सेवा मिलती है, जब तक स्थानीय शुल्क देते रहेंगे जब तक वे इस प्रणाली के किसी एक्सचेंज के 5 कि. मी. के अन्दर होते हैं और इससे जुड़े रहते हैं।

[सं. 3-7/85-पी.एच.बी.]

जे. के. छाबड़ा, निदेशक फोन (ई)

(TELECOM BOARD)

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 3883.—Whereas a public notice for revising the local area of Karvi-Chitrakoot Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (2c) of the Indian Telegraphs Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Karvi-Chitrakoot, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the publication on 15-3-1986 in 'Northern Indian Patrika' and 'Dainik Jagran' and on 17-3-1986 in Dainik Karmayug Parkash, and corrigendum published on 29-7-1986 in Northern India Patrika and 30-7-1986 in Dainik Jagran Newspapers ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (2c) of the said Rules, the Director General Department of Telecommunications hereby declares that with effect from 16-11-1986, the revised local area of Karvi-Chitrakoot shall be as under :

KARVI-CHITRAKOOT Telephone Exchange System :—

The local area of Karvi-Chitrakoot telephone system shall cover an area following under the jurisdiction of Chitrakoot Dham Karvi Nagarpalika ;

Provided that the telephone subscribers located outside the Chitrakoot Dham Karvi Nagarpalika limits but who are served from Karvi-Chitrakoot Telephone System will continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-7/85-PHB]

J. K. CHHABRA, Director Phones(E).

अभ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1986

का.प्रा. 3884.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्दन रेलवे, लखनऊ के प्रबन्धन से सम्बन्धित निवृत्तियों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-10-86 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 3884.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th October, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 45 of 1984

Reference No. L-41012/22/83-D. II(B) Jt. 14-5-1985

In the matter of dispute between :

Shri Uma Shanker,

C/o Shri B. D. Tewari, 96/196 Roshan Bajaj,

Lane Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

Senior Civil Engineer/Construction,

Northern Railway.

Lucknow

APPEARANCE :

Shri B. D. Tewari—for the workman.

Shri K. C. Jauhari—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41012/22/83-D. II(B) dt. 14-5-1985, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

Whether the action of the management of Northern Railway, in relation to their Senior Civil Engineer Construction, Lucknow in not providing employment to Shri Uma Shanker Chowkidar w.e.f. 17-3-1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. The case of the workman is that he was initially appointed as casual labour on 15-2-76 and worked till 16-3-82 and in this way had completed 1535 days of work during this span and he completed more than 280 days of work in several span. The workman was first of all illegally retrenched by PWI construction 2-3-81. The union raised objection and raised industrial dispute and in the earlier proceedings Sr. Civil Engineer (Const) agreed to take back workman on duty he was consequently taken back on duty on 15-9-81. The workman was not paid authorised scale of pay on which he again raised dispute before this honourable court on which the senior civil engineer construction and PWI Shri GS Bhatt fell enraged and terminated the services of the workman w.e.f. 17-3-82. It is averred that though his termination took place on 17-3-82 his services were terminated earlier on 15-3-82 and he was reappointed as gangman at Roza station on the same day i.e. 15-3-82 on the name of transfer from Lucknow to Roza knowing full well that casual workman are not liable for transfer, however, the workman continued to work at Lucknow on 15-3-82 and 16-3-82 and from 17-3-82 he was shunted out without any prior notice, notice pay or retrenchment compensation. He consequently is entitled to be reinstated with full back wages.

3. The management in its written statement took plea that the workman was never transferred to Roza but being work charged staff he was charged in the yard remodelling work of Roza with head quarters at Roza under the jurisdiction of Senior Civil Engineer Construction Northern Railway, Lucknow and also under the jurisdiction of P.W.I. The workman was never transferred but on completion of other works/handing over of the work to other incumbent the employee was charged against other sanction and shifted to other work charge sanction alongwith other staff for executing the work. It is further averred that the workman was never retrenched but absconded from duty from Roza w.e.f. 17-3-82 and never presented himself for employment. Information by P.W.I. vide letter dt. 27-4-82 was given. The management by way of written statement made para-wise reply and averred that if on 25-1-81 the workman was retrenched but he left on his own accord and left the store materials unattended at his place of duty and according to Railway Board circular dt. 8-6-81 a casual labour ceases to be on the roll if he remains on unauthorised leave for more than 3 days. After conciliation before ALC, the workman was given fresh appointment on 15-9-81 as labour to work on workcharged employee on post created for completion of any work, so workman can not claim any right. The management reiterated the stand that the management ever terminated the services of the workman w.e.f. 17-3-82, but he absconded from duty from Roza w.e.f. 17-3-82 but despite information he never returned for duty. That he was never terminated but on completion of their work and handing over the work to other incumbents the employee was charged against other sanction and shifted to other work charge sanction alongwith other staff for executing the work. In the end it is averred that at no stage or time the employee was retrenched but the employee himself absconded

from duty of his own accord, unauthorisedly and without informing the railway official and left the stores unwatched at the place of his duty. It is averred in the same sequence that it was legal and normal duty of watching the railway property in his charge before leaving his service and that the workman being project casual labour is not entitled to benefits of next below rule.

4. In the rejoinder it is averred on behalf of the workman that the workman was paid at Lucknow as Chowkidar upto 17-3-82 whereas the record shows that he was retained at Lucknow by employer.

5. In support of its contention the management has filed the letter of the Senior Accounts Officer (Const.) dated 8-3-83 testifying that the workman was paid for the period 15-3-82 to 16-3-82 vide pay sheet submitted by under VR No. 372 on 20-4-82 in presence of Shri G. S. Bhatt PWI construction (ii) Lucknow. The next documents filed is registration slip no. 1013 showing that a letter was sent to Uma Shanker workman, paper no. 3, is the letter of Sunder Lal Mate under his thumb impression intimating the PWI (ii) Lucknow informing that the workman attended duty on 15th and 16th and left for Lucknow by Siyaldah Express informing that he would not work at Roza, hence he is marking the workman absent from 17-3-82, 4th document is letter of PWI dt. 26-4-82 intimating the workman that he had approached him with the letter of Asst. Engg. Construction dt. 22-4-82 in which he was asked to employ the workman in project no. 116 for which work he did not come forward hence he was asked to contact him within a week else PWI would be helpless for want of vacancy. It appears that this letter was sent by registered post. The management has further filed letter addressed to Shri Bhatt to appoint him and Shri Uma Shanker was directed to go to project no. 116 on 22-4-82. The management has filed letter of management dated 10-3-82 whereby he has requested that he absent from duty to 26-1-81 to 12-2-81 on medical hence he be given scale rate of pay. The management has filed mustur-cum-pay sheet showing that the workman was present on 15th and 16th March, 1982 and was absent thereafter and in the end it is endorsed as left. The next document is the photo copy of the telegram showing that the workman was working as Chowkidar at JIU had left store unattended from 2-3-81. The management has filed the service sheet showing that the workman had worked as chokidar from 15-10-80 to 14-3-81 in broken period and his scale rate was discontinued from 26-1-1981.

6. In support of its contention, the management has examined 2 witnesses namely Shri G. S. Bhatt as M.W. 1 and in his affidavit has deposed about unauthorised leave from 25-1-1981 leaving the stores materials unwatched and without informing the railway authorities as a result of which he ceased to be on rolls after three days and he was given fresh appointment on 15-9-81, that he being a project casual labour was never authorised to scale of pay similarly he was never retrenched from 17-3-82 but he absconded from duty from Roza despite information by registered post on 17-4-82. He further averred therein that the workman was transferred to Roza but being a work charged staff he was charged for yard remodelling work at Roza with Head Quarters at Lucknow, and under the jurisdiction of the Civil Engineer Construction Lucknow.

7. In cross examination he admits that the workman was not transferred to Roza on 15 or 16-3-82. He further admits pay slip ext. W-1 dated 17-4-82 which shows that the workman was chowkidar and his wage period was from 15-3-82 to 14-4-82 and that for two days he was paid Rs. 14 at the rate of Rs. 7 per day. The witness however, states that designation chowkidar is written wrongly in ext. W-1 but admits that payment was made at Lucknow. He admits that Umashanker had obtained card pass from his office for going to Roza as Gangman, he further admitted that card pass register could be filed in court, it may be mentioned here that the management never filed any document to show that the workman under his signature obtained card pass for attending duty at Roza as gangman. He admits that the workman was made gangman from chowkidar on 14-3-82 when sanction of the post of chowkidar was expired and the post was transferred under P.W.I. Shri G. P. Singh where the workman refused to work. The management has failed to show that the sanction of the post of chowkidar was expired on 14-3-82 and it was on that account that he was transferred to Roza from 15-3-82 and exhibit W-1 shows that the post of chowkidar continued for the period 15-3-82 to 14-4-82 for which period he was paid for two days work at Lucknow on 17-4-82, before the witness i.e. after expiry of period of chowkidar, if the workman was not entitled to his two day pay between 15-3-82 to 14-4-82 on the post of chowkidar the management witness should not have signed it. From the fact that he has signed the document and in the absence of the document to show the post on which the workman was working earlier expired on 14-3-82 lend support to this contention that the post of chowkidar continued for the period 15-3-82 to 14-4-82 and it was two days work during this period possibly on 15-3-82 and 16-3-82 for which the workman was paid on 17-4-82. The management's own document paper no. 1 shows that the workman was paid for 15-3-82 and 16-3-82 in the presence of Shri G. S. Bhatt P.W.I. (I) Lucknow. This document falsifies the suggestion of Shri G. S. Bhatt in cross examination when he deposes that Ext. W-1 does not disclose for what two days he worked for which he got payments.

8. Management's another witness M.W.-2 is Mate Shri Sunder Lal. He deposed that in March, 1982 workman was working in his gang under his supervision at Roza and that he worked for two days i.e. 15-3-82 and 16-3-82 and absconded from duty w.e.f. 17-3-82 and he accordingly informed the PWI (II) about it. In his cross examination he admits that he was illiterate. He admits that one beldar under him was literate and he used to write names, according to him Umashanker workman was present on 15th and 16th March, 1982 and workman was in store and was not digging earth for earth work. He further states that workman has not brought with him any letter of PWI when he met him for duty. He further admits that prior to that workman was not working with him. He further admits that Shri Bhatt did not visit Roza on 15th and 16th March, 1982 but had verbally told him on 14th March, 1982 that the workman may be taken on duty while he was leaving Roza for Lucknow. He further stated that the workman had gone Roza on 14th by some night train but later resiled and stated that he did not know by which train the workman had reached at Roza. It is strange that the workman was taken on duty by Sunder Lal on the verbal instruction of Mr. Bhatt at Lucknow, in the absence of any document to show that project work commenced at Roza from 15th March and the workman was working at

store camp and card pass by management was issued to him under these circumstances I am not inclined to believe this witness and it appears that the paper no. 8 filed by the management was prepared later on the instructions of the PWI. Admittedly all this is in English and must have been prepared by some one else other than Sunderlal.

9. On behalf of workman two witness have been examined out of which WW1 is workman himself and in his affidavit he has reiterated the case set out in the claim statement. He had given two affidavit one is dated 13-12-84 and the other is dated 8-8-85 and in the earlier affidavit he simply reiterated the stand taken in the claim statement and in the next affidavit dated 8-8-85 is regarding submission of medical certificate dated 15th and 16th March, 1982 showing that the said document is genuine. The certificate is dated 14-5-85 issued by Dr. SZHR Baraha on 14-5-85 showing that the workman was suffering from Dytia from 15 to 16th March, 1982 and was advised treatment and rest for two days. He too has been examined as WW. 2 Workman in his cross examination has deposed that despite his illness he attended duty and obtained medical certificate later. He deposed that he was chowkidar of PWI G. S. Bhatt and the work of Shri Bhatt was doing in Lucknow as well as at Roza on those days. He has denied the management's suggestion that Shri Bhatt P.W.I. had no work at Lucknow on 15th and 16th March, 1982 and no material was lying at Lucknow at that time. He has emphasised that he had line sleepers at Lucknow which were given under his supervision at Lucknow it may be during that line sleepers were given to him as Shri Bhatt PWI was instructed with the work of remodelling of yard for additional facility at Roza. The workman has deposed that all that was kept under tent in the camp office.

10. Dr. Zahuriddin M.W. 2 has proved his certificate WW2 in cross examination he admits that he had a register for issuing certificate which he has not with him at the time of deposition and he has not noted any reference number in his certificate. He however, stated that while suffering from Dytia one can work. His evidence in the absence of treatment register certificate issuing register and particularly the fact that certificate was issued about 3 years later in May, 85 about treatment in March, 1982 does not inspire confidence. I fail to understand why this certificate at all obtained and the witness examined when admittedly he worked on 15th and 16th March, 1982 and thus I am not inclined to believe him on the point that the workman was at Lucknow on those days if purpose of his deposition is that but I am inclined to believe the workman on this point which emerges from Ext. W-1 that he was chowkidar for the period 15-3-82 to 14-4-82 and that he was paid at Lucknow before Shri G. S. Bhatt on 17-4-84. It appears that payments for two days was made to the workman on the instructions of Shri G. S. Bhatt, P.W.I. when he was making efforts for being taken on employment and it was on this count that soon after on 26-4-82 P.W.I. (II) wrote to the workman that on the instruction of Assistant Engineer Construction he was required to attend project no. 116 but he did not go for duty. The management's letter dated 19-4-82 addressed to Shri G. S. Bhatt shows that the workman was directed to go on 24-4-82 to project no. 116. In these circumstances and for the reasons discussed above I am inclined to believe that the workman was cease to work from his chowkidar duty w.e.f. 17-3-82 whereas he was required to work for the period 15-3-81 to 14-4-82. The workman was issued service certificate by the CSE Northern Railway showing that the workman worked either as chowkidar or gangman from 15-12-76 to 16-3-82 in broken period and in one span or year counting back word from 16-3-82 he worked for 183 days. The management has not filed any document to show that the workman was working on project despite averments in the written statement to that effect on 3-7-86

management moved an application filing two documents alleging that the management had taken plea from the very beginning that the workman was daily rated casual labour on project for remodelling of yard for providing additional facility at Roza. He has filed true copy of the sanction of the abstract works programme 1979-80 of item no. 372. The paper filed by the management shows that item no. 372 was regarding remodelling of yard for additional facility at Roza, the payment record filed by the management shows that pay sheet was submitted as no. 372, the payment receipt ext. W.1 filed by the workman suggests that one period was for the period 15-3-82 to 14-4-82 and according to workman rails were put in his charge at Lucknow for watching as chowkidar. All this suggests that the workman was employed on project no. 372 which work was to continue from 15-3-82 to 14-4-82 and that after working for two days i.e. 15-3-82 and 16-3-82 the workman was ceased to work without any justifying cause.

In its application management stated that the workman absconded from duty consequently not providing him work from 17-3-82 as chowkidar was not justified. The result is that the workman will be reinstated on the said post from 17-3-82 with full back wages.

I, therefore, hold that the action of the management of Northern Railway in relation to their Senior Civil Engineer (Construction), Lucknow in not providing employment to Shri Uma Shanker Chowkidar w.e.f. 17-3-1982 is not justified. The result is that he will be reinstated on the said post with effect from 17-3-82 with full back wages.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the government for its publication.

Dated : 3-10-86.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41012/22/83-D.II(B)]

HAPI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

का.आ. 3885.—केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, सी. पी. डब्ल्यू. डी. मजदूर यूनियन, नई दिल्ली, करती है के बीच हुए माध्यस्थता करार को श्रम मंत्रालय के दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 के आदेश संख्या 42013/1/86-डी-2(बी) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त संदर्भ में उल्लिखित व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3क) के अनुसरण में एतद्वारा उन नियोजकों और कर्मकारों की जानकारी के लिये सूचना देती है कि जो माध्यस्थता करार के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन उक्त विवाद में संबंधित हैं, उन्हें अपने मामले उक्त माध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

[सं. एल.-42013/1/86-डी.-2(बी)]

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 3885.—Whereas in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government has published the arbitration agreement between the employers in relation to C.P.W.D. Nirman Bhawan, New Delhi and its workmen represented by the General Secretary, C.P.W.D. Mazdoor Union, New Delhi in the Gazette of India vide Ministry of Labour Order No. L-42013/1/86-D.II(B) dated 31 October, 1986.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the persons in the reference represent the majority of each party:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3A) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby notify for the information of the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute that they shall be given an opportunity of presenting their case before the Arbitrators.

[No. L-42013/1/86-D.II(B)]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

आदेश

का.आ. 3886.—भारत सरकार में तत्कालीन श्रम तथा पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2251 दिनांक 21 मई, 1983 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एम. के. बंसल को 23 अक्टूबर, 1986 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-11016/1/86-सी एल टी]

New Delhi, the 29th October, 1986

ORDERS

S.O. 3886.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, Chandigarh constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) No. S. O. 2251 dated the 21st May, 1983.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri M. K. Bansal, as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 21st October, 1986.

[F. No. A-11016/1/86-C.I.L.T.]

का.आ. 3887.—भारत सरकार में तत्कालीन श्रम तथा पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2252 दिनांक 21 मई, 1983 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एम. के. बंसल को 21 अक्टूबर, 1986 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-11016/86-सी.एल.टी.]

श्रा. टी. पाण्डेय, उप सचिव

S.O. 3887.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, Chandigarh constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) No. S. O. 2252 dated the 21st May, 1983,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri M. K. Bansal, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect from 21st October, 1986.

F. No. A-11016/1/86-C.L.T.]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

ई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का.ग्रा. 3888.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सिंगरेणी कोलरीज कं. लिमिटेड, कोठागुडम डिवीजन, पो. वेंकटेशखानी, जिला खम्मम (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3888.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P. O. Venkateshkhan, Distt. Khammam (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

Industrial Dispute No. 19 of 1984.

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District (A.P.)

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District.

APPEARANCES :

Shri D. S. R. Varma, Advocate for the Workmen.

Sarvastri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Miss G. Sudha, Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation by its Order No. L-22011/117/83-D. III(B) dated 2nd March, 1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division P.O. Venkateshkhan, District Khammam and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem are justified in not sending Sri Thalla Durgai, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station for assessment of his age and retiring him on 31-1-1983. If not, to what relief is workman concerned entitled?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 19 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman Thalla Durgai, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station, appealed to the Management of Singareni Collieries Company Limited, to confirm his age particulars as recorded in the Bonus Card wherein it was stated very clearly that his age was 25 years as on 14-12-1957, the photostat copy of the

same is enclosed also. According to him he has to retire during the year 1992 after attaining 60 years of age as per the Company Age Retirement Rules. But the Management stated he was sent to hospital during January 1973 for assessment of his age and his age was assessed by the Medical Board as 50 years as on 23-1-1973. In other words he has to retire on 23-1-1983 this aspect of the matter was brought to the notice of the Management by he affected party to send him to assess his age correctly. The Management should have sent up as per the Circular dated 6-7-1981 which is enclosed as Annexure 2. The Management normally should have sent Thalla Durgai for medical examination instead of retiring him on 31-1-1983. Thus the Management denied the natural justice and they did not give him fair opportunity to the workman in assessing his age according to Bonus card and other records of the Management. The Management should have corrected his age as per records provided by the workmen through Age Determination Committee/Medical Board by doing natural justice. Therefore when the same is not done and when they want to retire him on 23-1-1983 they requested that the same is illegal and to declare the same as not justified and grant him all the reliefs as prayed for.

3. The reference is received in this Tribunal on 7-3-1984 and the claims statement is filed on 21-4-1984. The Management filed its counter on 28-4-1984.

4. It is mentioned in the counter filed by the Management that it was a fact that Thalla Durgai, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station was appointed in the Company on 31-3-1948. According to them as his age was not assessed at the time of his appointment he was sent for Medical Board on 23-1-1973 and the Medical Board by its letter dated 23/29-1-1973 has confirmed that Thalla Durgai was 50 years as on 23-1-1973. The Union claimed that Durgai was only 25 years as on 14-12-1957 as per Bonus Card is not correct because the bonus card does not stipulate the age of Thalla Durgai as 25 years as on 14-12-1957. The Bonus Card only speaks about the preparation for bonus card and not age of the worker as on that particular date. The Medical Board rightly after examining the worker confirmed the age of 50 years as on 23-1-1973. The Argument of the Union that Thalla Durgai was absent on 23-1-1973 at the time of age assessment before the Medical Board is false as the said Thalla Durgai was present and inscribed his thumb impression in the Medical Form before the Medical Board. The true copy of the age assessment by the Medical Board of which Thalla Durgai thumb impression has been inscribed is enclosed herewith. It is clearly indicated that Thalla Durgai did not present before the Medical Board and accepted his age as 50 years on 23-1-1973. As such he cannot dispute the age after a lapse of 10 years and that too at the verge of his retirement. The Circular dated 6-7-1981 quoted by the Union does not stipulate anything to send the worker for age assessment when his age has been already assessed by the Medical Board. So there is no justification in the Union's demand of again referring Thalla Durgai to the Medical Board for his age assessment.

5. There afterwards after number of adjournments the Workman was examined on 25-6-1985. He was cross-examined also. According to W.W1 the original bonus card issued of him for which xerox copy is taken is marked as Ex. W1. He is an illiterate person. It is his case that he was 25 years old when Bonus card was issued to him on 14-12-1957 and that he should retire at the age of 60 years. As per the bonus card Ex. W1 he should be in service till 1992. He denied that he was examined by the Medical expert at the instance of the Management on 23-1-1973. According to him they gave notice as per Ex. W2 on 7-11-1982 and he also relied upon the Circular dated 6-7-1981 to substantiate his case that he should have been referred to the Age Determination Board or Medical Board. He denied that the Union entered into an agreement with the Management in 1961, 1965 and 1969 and the Management sent those employees whose age was in dispute to the Medical Board for determining their age. He also denied that he approached the Management to decide his age correctly by referring to the Medical Expert and Dr. D. Anjeneyulu determined his age as 50 years on 23-1-1973 after examining him as per

Ex. M1. He denied that he put his thumb impression on Ex. M1. It is his case that he cannot identify his own thumb impression on the deposition as well as the document shown to him Ex. M1. The ten L.T.s were taken in the open Tribunal for the purpose of comparison and for the purpose of comparison and identification Ex. M2 is the L.T.I. sheet. He denied that his age was already determined as 50 years as on 23-1-1973 and therefore he need not be sent for medical examination for determining the age again. He denied under Ex. M3 and M4 that the Management followed the procedure required for determination of his age properly. He admitted that he had taken gratuity and Provident Fund after retirement.

6. Thereafterwards the Management took number of adjournments Prior to that even on 29-9-1985 the Management reported that the talks of compromise were going on. So 29-9-1985 to 25-11-1985, no settlement was reported and no evidence is adduced by the Management and finally a Memo was filed on 10-12-1985 stating that the talks of settlement are going on between the union and the Management as such the matter may be adjourned for another 20 days. On 15-1-1986 as no settlement or agreement is filed between the parties, the Tribunal posted for the evidence of the Management on 14-2-1986.

7. From 14-2-1986 the matter is adjourned to 24-3-1986, 1-4-1986, 30-5-1986, 1-8-1986, 25-8-1986, 10-9-1986 and 22-9-1986 and as there was no interest evidenced by the Management, the matter was decided on merits on the file and records and evidence as other side was opposing for granting of any adjournment stating that it is already delayed.

8. On 10-9-1986 the Management filed a Memo which is numbered as M.P. No. 310/86 stating that they filed petition in I.D. No. 41/85 on 3-9-1986 stating that they are not proceeding in the above matter as they are moving the application for transfer of this case from this Tribunal to another Tribunal as such it may be deferred. That Memo was rejected on 10-9-1986 stating that in view of the orders passed in M. P. No. 278/86 in I. D. No. 41/85 on 4-9-1986 this Memo is rejected. By that time no Writ is filed as averred in their petition that they are moving the matter against I. D. No. 41/85 on 3-9-1986 and further there was no intimation also seeking adjournment in this case or further expressing their difficulties if any.

9. Even afterwards the Tribunal was considerate and adjourned the matter from 10-9-1986 to 22-9-1986 and finally as there was no representation on the available data material, the matter was proceeded with. Now the workers relied upon his date of birth that he was aged 25 years as per Ex. W1 which is a Bonus card given to him. Admittedly he is an illiterate markman working as Scraper Khalasi since 1957. He denied having been examined by the Medical Board regarding the assessment of his age on 23-1-1983, by a Medical Board expert Dr. D. Anjaneyulu. He denied this Ex. M1. On the other hand he filed that he was asked to retire as per Ex. W2 on 31-1-1983 and that he had no knowledge of the other documents. He relied upon Annexure 2 of his claims statement which is marked as Circular dt. 6-7-1981 issued by the Management. It is mentioned that in Ex. M3 also to that affect. The procedure also mentioned regarding the determination of verification of age assessment. In the case of illiterates the date of birth will be determined by the Colliery Medical Officer keeping in view any documentary or other relevant documents as may be produced by the appointee and date of birth so determined should be treated as correct date of birth and the same will be altered under any circumstances. Whenever there is no variations in records such cases will not be reopened unless there is glaring and apparent entry brought to the notice of the Management. The Management after being satisfied on the merits of the case will take appropriate action for correction through Age Determination Committee/Medical Board. Now it is his case that he never approached before the Medical Board on 23-1-1973. He denied Ex. M1. Now when the workers denied Ex. M1 and also specifically stated that he knew Dr. D. Anjaneyulu but it is not correct that Dr. Anjaneyulu determined his age as 50 years on 23-1-1973 after examining him as per Ex. M1 and when Ex. M1 thumb impression is questioned, the Management failed to examine the Junior Engineer, Sand

Gathering Station who is alleged to have signed it to show that he said assessment of age to prove that he was present when Dr. D. Anjaneyulu examined. The thumb impression of the workman is disputed rightly by the workman as an illiterate person stating that he cannot identify his thumb impression. Now the Management took some samples of 10 L.T.s. which was marked as Ex. M2 in this open Tribunal but still they were not bold enough to send them to the Finger expert or Thumb Impression Expert to connect the thumb impressions on Ex. M2 with Ex. M1 as they were done by the same Thalla Durgajiah i.e. the worker involved. Having taken thumb impression on 25-6-1985 when the Worker was being examined; when no steps were taken for about more than a year and when they dragged the matter on the pretext of settlement stating that they are compromising an agreement with the workman and his Union and when they did not and could not come out with the said Settlement for more than a year and when they failed to examine their witnesses in support of Ex. M1, the Circulars under Exs. M3 and M4 come into effect. In other words when there is no verification of records such cases will not be reopened unless there is glaring and apparent wrong entry brought to the notice of the Management. In the instant case there is no record to show that the Management gave notice to him that there is glaring and apparent wrong entry under Ex. W1 and thus he was examined by the Medical Board as sought to be explained. When Ex. M1 is not proved according to law and Management witnesses could not come into witness box for more than 1-1/2 years and when Ex. M1 is denied by the witness stating that he was never examined on 23-1-1973 by Dr. D. Anjaneyulu whom he knew; when there is no other evidence to disbelieve him, it must be held that the argument of the Management that he was examined on 23-1-1973 under Ex. M1 is not true and correct. Ex. M1 is marked subject to proof and relevancy in the said circumstances, if Ex. M1 goes as not proved document, the oral evidence read with Exs. M3, M4 coupled with Exs. W1 and W2 would show that the retirement of the workman on 31-1-1983 holding him that he completed 60 years of age is incorrect. Ex. W1 and oral evidence of workman which stand unrebuted would show that he is entitled as per Ex. M2 to be continued till 1992 and the management evidently took number of adjournments on the pretext of settlement and were talking for the best reasons known to themselves without even adducing oral evidence for more than 1-1/2 years. Moreover it need not be stressed as per I. D. Act the workers case should be disposed of in a stipulated time of three months from the date of reference if it is an individual case or within period of six months if it is a case involving more than one worker and looked from any angle this kind of delay without any explanation would only add to the misery of the worker who is involved in this reference while the Management is quite happy in dragging on for reasons best known to them, and it cannot be said that they should have been given further opportunity to prove their case.

10. Thus on a careful consideration I held that the action of the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagundem is not justified in not sending Sri Thalla Durgajiah, Scraper Khalasi Sand Gathering Station without any proper assessment of age by the Medical Board or Age Determination Board from 31-1-1983. The said action is unjustified and therefore the workman is entitled to all the reliefs and he is deemed to be in service continuously from that date of his retirement during this period also with back wages and attendant benefits and he should be continued till 1992 in the given circumstances.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 4th day of October, 1986.

Sd. (Illegible)

Industrial Tribunal

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined
for the Workmen :
WW1 T. Durgajiah
Witnesses Examined
for the Management :
NIL

Documents marked for the Workmen :

- Ex. W1 Bonus Card pertains to T. Durgalah.
- Ex. W2 Letter dt. 7-11-82 addressed to T. Durgalah by the Asst Engineer, Aerial Ropeway & Sand gathering Station, S.C. Company Limited, Kothagudem with regard to retirement from company's service.
- Documents marked for the Management :
- Ex. M1 Letter dt. 27-12-72 addressed to T. Durgalah by the Junior Engineer, Sand Gathering Station, S.C. Co. Ltd., Kothagudem with regard to assessment of age.
- Ex. M2 Ten L T. Is of T. Durgalah.
- Ex. M3 True copy of the Circular No. P49/3533/1981 dt. 6-7-81 issued by Chief General Manager, S.C. Co. Ltd., Kothagudem to all Pits and Departments all collieries with regard to procedure for determination/verification of the age of the employees.
- Ex. M4 True copy of the procedure for determination/verification of age of the employees.
- Dt. : 7-10-86

S. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. L-22011/117/83-D. III(B)]

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का.प्र. 3889-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सिंगरेणी कोलरीज लिमिटेड, मण्डामर्री, पो. कल्याणीखानी, जिला-अदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधकों से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3889.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad (AP) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri, P.O. Kalvankhani District Adilabad (AP) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 84 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri, Adilabad District.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri, Adilabad District.

APPEARANCES :

Sarvaswari M. Pandu, Ranga Rao and B. G. Ravinder Reddy, Advocate for the Workmen Sarvesri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal, and Kumari G. Sudha, Advocate for the Management

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/3784-D. III(B) dated 20-11-1984 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and their workman to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur Division I in dismissing Sri G. Laxminarayana, Terax Labour Operator with effect from 2-6-1984 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 84 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman that the punishment is very heavy and disproportionate compared to the charge alleged and the order of dismissal is bad in law as the same is against the Standing Orders of the Company and that his right of appeal is denied as the orders are passed by the General Manager instead of Manager as per the Standing Orders.

3. Of course the Management filed a counter that G. Laxminarayana was given full opportunity to defend in the domestic enquiry conducted on the charges and on the basis of the allegations being proved, the dismissal order was served by the General Manager who is appropriate authority to issue dismissal orders. According to them the right of appeal to the Appellate Authority namely Executive Director/Chairman and Managing Director who is above General Manager is not dispensed with and therefore he should have any grievances for the same. It is also mentioned that the offence is a serious one and would have resulted in heavy damage to the Company property and the punishment awarded to him is not at all disproportionate.

4. The Management examined two witnesses as M.W.1 and M.W.2 and marked Exs. M1 to M9 and the Workmen examined one witness as W.W1 and marked Exs. W1.

5. When the Management filed a Motion to decide the preliminary point regarding the validity of the domestic enquiry, the said witness and evidence was adduced before this Tribunal by both parties and elaborate orders, on hearing both sides, was passed by me on 12-6-1985 holding that the domestic enquiry was conducted fairly and no illegality was committed by the Management and the principles of natural justice was fully observed and the enquiry was fair and proper. It is part of the record.

6. The afterwards the matter was adjourned to 11-7-1986. The matter went through number of adjournments from 11-7-1986 to 19-8-1985, and to 22-8-1986 and finally to 4-9-1986 when the Management filed a petition which is numbered as M.P. No. 235/86 stating that they filed a petition in I.D. No. 41 of 1985 dated 3-9-1985 in this Tribunal and they are not proceeding further in the above matter and they are moving an application for transfer of all their cases including this matter as stated in that petition in I.D. No. 41 of 1984 and as such hearing may be deferred. The workman counsel filed a counter stating that the allegations that the management cannot proceed with this case for he reasons stated in their petition in I.D. No. 41 of 1985 is unreasonable and unjustified and they are no way concerned with the said case and the management should have taken steps to engage another counsel if the counsel is not prepared to proceed with the case before the Tribunal and the workman cannot be put to irreparable delay tactics just because the counsel wanted not to proceed with the case in this Tribunal and counsel for the workmen stated that matter should be heard in the interests of the justice. On that the order was passed reflecting the same as both matters have no relevance as they are not connected also.

7. As per the charge sheet Sri G. Laxminarayana Terax Loader Operator who was engaged in first shift on 29-1-1984 to lift stock of coal at M.K. No. 4 Incline at about 11.30 a.m. was not found on Terax Loader but in his place one

Chandragiri Rangaiah, General Mazdoor was found operating the Terax Loader for about ½ an hour and that this affected the lifting of coal and this amounted to misconduct under Standing Order 16(1), (2) and (2). New under Standing Order 16(18) leaving work without permission is a misconduct, under Order 16(2) causing damage to work in progress or to the property of the Company amounts to misconduct, under Order 16(2) theft, fraud and dishonesty in connection with the Company business or property is also defined as misconduct. For these things it is said an employee may be suspended, fine or dismissal without notice or any compensation in lieu of notice if he is found to be guilty of misconduct. Now as per the evidence of M W2 who is the Additional Chief Mining Engineer Bellampally that A. Prabhakar, Junior Engineer as Acting Manager C.S.P., Ramakrishnapur and Ex. M1 is the chargesheet issued by the Executive Engineer who is the head of the Department, Ramakrishnapur Division I and as per Ex. M5 the enquiry proceedings and the report Ex. M6, it is established that at the relevant time he was Terax Loader to lift stock of coal at M K. No. 4 Incline. The explanation given by him is marked as Ex. M2. The workman stated that he worked till about 12 noon and that he left the place for taking tea and therefore the allegation that he was not present bodily is not correct. It is his case that about 12.30 noon Additional C. E. and D.E., RKP I came to the Loader and at that time he came in opposite direction and the Helper mazdoor who was with him was found operating Terax Loader as per them. He mentioned that the Helper Mazdoor did not know how to operate Terax loader and promised to know the exact facts. In the explanation it is his case that Additional C.E. and D.E., RKP I left the place and that he verified from Chandragiri Rangaiah that he did not operate the Loader and requested that the charge sheet should be withdrawn. He examined one witness by name Bhasker Rao in defence to support that the said Chandragiri Rangaiah, General Mazdoor who was attached to the Terax Loader and brought water and poured into the radiator and he was trying to stop running of the Terax Loader by pulling stop liver which is in the Loader cabin and where he was asked why he was in the cabin, told him to get down as the Additional C.E., and Senior D.E., RKP I came there and then Chandragiri Rangaiah got down from the Loader and within 10 minutes G. Lakshminarayana, Driver who was operating Terax Loader came there and had a discussions with the above Officers. In fact he asked in the cross examination by the management why he brought the lorry API 3550 if the Terax loader was not running for loading as it might likely to cause accident. The witness answered that he did not bring the lorry near to the Terax loader and the coal heap was in front of the loader. He was asked how much time he waited at the coal for loading the coal with his lorry, he mentioned that he waited for about 10 minutes. He was asked why he was present when the Terax loader was not present. He answered that he did not see it. He sat in the lorry cabin. He explained when engine is hot, water will not be poured in the radiator and while pouring water in the radiator he will keep Engine running. In fact there was no question put to him to this defence witness Bhaskar Rao by the Management witnesses to show that this Chandragiri Rangaiah was seen operating terax loader and that this Driver Bhasker Rao was not present when the Additional C.M.E. and Senior D.E. RKP came there. So it cannot be said that the evidence of M. Bhasker Rao can be brushed aside very lightly. He defended and explained that Chandragiri Rangaiah never operated this Terax Loader. The explanation of G. Lakshminarayana would also show that the engine worked for a long time and it was not. Hence after pouring water in the radiator the engine should be stopped and he asked mistry to get water from M.K. 4, Incline and to stop engine. So he did not take the ignition key as the mazdoor is working with Terax Loader permanently since one year. He asked the mazdoor to stop engine after pouring water in the radiator, and he also explained that when he left the Terax Loader he locked emergency brake and even that day he did the same. So the explanations of G. Lakshminarayana as well as the witness Bhasker Rao would show that the allegations as contemplated under Clauses 16(9) and 16(2) is not established because there is no proof of causing damage to the work in progress or to the property of the Company or any dishonesty in connection with the business of the Company or property that he left for 10 minutes for taking tea while the mazdoor was asked to pour water when the Terax Loader engine was hot as

defended by him and also supported by Bhasker Rao defence witness is not vitiated by any suspension and there is nothing in the cross examination done to them that Bhasker Rao was not present when the Additional C.M.E. and D.E., RKP I came there and he was not at all present and he was only a brought up witness. So Chandragiri Rangaiah is an admitted General Mazdoor and he was therefor about one year and he was helping the Terax Loader. There is no evidence that something was lost or damaged except stating that the lifting of coal was affected which is not proved by any statistical data maintained by the management to show that there was no coal loading at all. There is no proof of dishonesty except alleging that there is "dishonesty" when he left for having tea. The three charges levelled against the workman are that Chandragiri Rangaiah was operating the Terax Loader. It is disputed by G. Lakshminarayana as well as his statement as supported by Bhasker Rao. Chandragiri Rangaiah is not examined by the Management to support their case. Surprisingly the said Chandragiri Rangaiah who was found operating was not given a charge sheet. If Chandragiri Rangaiah was found sitting in the cabin, it cannot be said as an offence on terax loader alone under the Standing Orders. The delinquent case is that he was absent for 15 minutes and there is therefore no loss of loading stock of coal and even Junior Engineer who is examined in the domestic enquiry P.W3 mentioned that lorries could not come for loading and so there is no loss of loading of coal into the lorries. The third charge is about dishonesty. Even about dishonesty, there is no proof. Enquiry Officer could not make out any proof of dishonesty for the absence of 15 minutes or 30 minutes as the case may be simply because helper was sitting in the cabin and when there is any loss of production or damage to the machinery proved; without penalising the concerned workman or without examining the said Chandragiri Rangaiah who was the real delinquent equally responsible for such a mistake. When there is no proof that the said Chandragiri Rangaiah had done the operation of the Terax Loader at the instance of Lakshminarayana. It is surprising that the management thought fit to award the maximum punishment of dismissal to him having considered the entire facts and also the nature and the gravity of the offence when the evidence in relation to the matter is not satisfactory to hold that the same resulted in heavy damage to the Company property and the persons involved in the Company by the tangible evidence without any other bad record; I am of the opinion that it is a fit case where Section 11-A of the I.D. Act has to be given effect while considering on the punishment having been satisfied that the order of dismissal was not justified. Section 11-A is incorporated in the I. D. Act, 1947 to give power to the Tribunal in case wherever necessary to set the order of dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any as it deems fit or given to such other relief to the workman including award of lesser punishment as the circumstances may require. Now the material on record as produced before me do not show that there is any dishonesty proved so as to hold that there is misconduct. The evidence of G. Lakshminarayana who is the alleged delinquent as well as Bhasker Rao the lorry driver who was examined were not shattered that the Terax Loader engine got heated and the labour was asked to pour water in the radiator and thus the expression misconduct as contemplated under Standing Order 16(2), 16(18) and 16(9) had no application, to show the improper behaviour of intentionally doing wrong or doing deliberate violation or rules or standing orders. For offences of trifling nature if works is obdurate holding such things would constitute an act of "misconduct" then it becomes that the Management can exercise an unbridled power and terminate every worker on some pretext or other for offences of trifling nature. The charge of misconduct, therefore, is the charge of some positive act or of conduct which would be quite incompatible with the express and implied terms of relationship of the employee to the employer. What is misconduct will naturally dependent upon circumstances of each case. In the instant case it is not proved beyond reasonable doubt that deliberate disobedience of any orders of superior authority to hold it as misconduct. Further there is no proof of any loss to the employer. Further this so called misconduct must have direct connection with the commitment or comfort of the workman at work, even that is lacking. Moreover there is no material bearing on the smooth efficient working of the concern. Thus when there

is no proof that he is habitually avoiding work and entrusting to his helper and sitting idle and when there is no proof of loss of property and damage to any materials and when there is no proof of wilful insubordination or disobedience even such mistakes were pointed out or that he was in the habitual negligence doing neglect of work it cannot be misconduct. Even from the language of the Model standing Orders it is clear that it does not define "misconduct" or "illustrate it exhaustively". Thus on a careful consideration of the entire matter I hold that it is a fit case where the dismissal order passed is quite disproportionate and very heavy compared with the charges alleged even if proved and therefore the order of dismissal is set aside. The period from the date of dismissal is set aside. The period from the date of dismissal i. e. 2-6-1984 till this date of passing of the award is treated as a period without pay but the same will have to be treated as continuity of service and the person is directed to be reinstated from this date as on duty with wages as Terax Loader.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 4th day of October, 1986.

Sd/-Illegible
INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

Sd/- Illegible

Witnesses Examined
for the Management

Sd/-Illegible
Witnesses Examined
for the Workmen :
W. W1 Laxminarayana

M. W1 S. Janardhan Rao

M. W2 S. K. Garg

Documents marked for the Management

- Ex. M1 Charge Sheet dt. 1-2-1984 issued by Executive Engineer, CSP-RKP to G. Laxminarayana, Terax Loader Operator.
- Ex. M2 Explanation dt. 4-2-84 given by G. Laxminarayana to the Executive Engineer, CSP, R.K.P.
- Ex. M3 Enquiry Notice dt. 9-3-1984 issued by Executive Engineer CSP, RKP to G. Laxminarayana.
- Ex. M4 Enquiry Notice dt. 14-3-1984 issued by Executive Engineer CSP, RKP to G. Laxminarayana.
- Ex. M5 Enquiry Proceedings Pertaining to G. Laxminarayana.
- Ex. M6 Enquiry Report pertaining to G. Laxminarayana.
- Ex. M7 True copy of the letter dt. 4-10-83 addressed by Addl. CME, RKP, I to all Pits & Departments with regard to S. Janardhan Rao, P.O. will conduct domestic enquiries in the Pits and Departments of RKP. I division with effect from 5-10-83 in place of R. Narasimha Reddy.
- Ex. M8 Letter dt. 13-3-84 addressed to the Director General of Mines Safety, Dhanbad, Eastern Rly. and to the Director of Mines Safety, Hyderabad Region, Hyderabad by the Additional Chief Mining Engineer Ramakrishnapur Division I with regard to A. Prabhakar Junior Engineer authorised to act as Manager, C.S. Plant, Ramakrishnapur from 13-3-84 till Yadagiri resumes duty who went on leave from 13-3-84 to 16-3-84.
- Ex. M9 Letter dt. 5-2-84 addressed by G.M. M.M. and RKP to M. Yadagiri with regard to privilege leave.

Documents marked for the Workmen :

Ex. W1 Dismissal Order dt. 1-6-1984 issued to G. Laxminarayana by the General Manager, M. M. & RKP.

Dated : 8-10-86.

[No. L-22012/37/84-D.III(B)]
J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1986

का. आ. 3890 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, म. सिंगरेणी कोलरीज कं. लिमिटेड, कोठागुडम, डििविजन, पो. वेकटेशखानी, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd November, 1986

S.O. 3890.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad (AP) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P.O. Venkatesh Khani, District Khammam (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 17 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District A.P.

AND

The Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District, A.P.

APPEARANCES :

Sri D. S. R. Varma, Advocate—for the Workmen.
Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Kumari G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation by its Order No. L-22012(109)/83-D.III(B) dated 28-2-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division P.O. Venkatesh Khani District, Khammam A.P. and their Workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem were justified in not calling Shri Kudipudi Suryanarayana acting as Munshi with effect from 28-7-1981 for selection to the post of Munshi on a regular basis and not confirming him as Munshi. If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 17 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman, it is mentioned that he was working as Trammer, No. 5 Incline and he was not called for interview for selection of Munshi by the Management on the plea that he is not a senior candidate alongwith other eligible Trammers. According to him the Management did not fix any norms prior to the selection and there is no promotional policy for selection of Munshi and there was no such agreement or approved policy even by the Union. It is his case that as per the Company rules right from the date i.e. 28-7-1981 he is acting as Munshi and he was paid acting allowance as per the Company rules and the vacancies caused in 5 Incline due to medically unfit of a permanent Munshi by name Chitakabathula Narasiah. It is also his case that the Management after verifying amongst the other Trammers to do that job, but none are interested to act as Munshi nor they have called for acting Munshi post. So it is asserted that Kupudi Suryanarayana is doing his job from 27-1-1981 onwards without having any adverse remarks and he should be confirmed as per the Company Standing Orders vide No. 2(1). As he was continuously working till the date of filing of this application to the satisfaction of his superiors. According to him when he claimed for confirmation the Management denied confirmation and they have conducted interview by calling the senior most Trammers in Category I by adopting promotional policy without having any conformity with Unions. Thus it is his case that as he was working continuously till 28-7-1981 he should be made permanent with retrospective effect as per principles of natural justice.

3. The reference was made to this Tribunal on 3-3-1984. The claims statement was filed by the Workman on 4-7-1984. The counter was filed by the Management on 22-12-1984 i.e. after 54 months after filing of the claims statement.

4. In the counter filed it is stated that the petition is misconceived under the rules and Standing Orders. It is admitted that Sri K. Suryanarayana, Trammer working in 5 Incline was acting as Munshi in Grade III in the place of Sri C. Narasiah from 28-7-1981 as later has been declared medically unfit for further service. It was also true that he was being paid acting allowance as per the rules for the duties discharged by him as Munshi. But it is incorrect to say that there is no promotional policy for selection of Munshi and that it was not proved or agreed by the Union. The framing of promotional policy is a managerial function and the workers have no right to interfere with regard to promotional policy. It is submitted that according to their promotional policy circulated by the General Manager by his letter dated 2-5-1976 to fill up the vacancies of Munshi, area seniority of Trammers was taken into account. So the Divisional Heads of Kothagudem, Yellandu and Manuguru were asked to submit the list of senior-most Trammers to be considered for the promotion of Munshis. There are guidelines given in the Circular since 1976 for selection of Munshi. As the post is temporarily vacant Sri K. Suryanarayana was called upon to act as Munshi from 28-7-1981. After calling for the particulars from the senior-most Trammers out of the three Divisions for the post of Munshis, interviews were conducted since Sri K. Suryanarayana was promoted as Trammer on 15-12-1984 as there were number of other seniors who were eligible for promotion, he is not called for interview. No junior to K. Suryanarayana was called for interview. The job of munshi is mere of clerical in nature and it has to supervise to coordinate with the Trammers which are to enable the Trammers to discharge their duties. The definition of permanent employee under Standing Order 2(1) had nothing to do with the promotional policy. No workman has a right to demand for promotion on the basis of their acting experience which is temporary in nature. No principles of natural justice were involved and the Management is right in not confirming him as Munshi and the petition is liable to be dismissed.

5. The workman examined himself as WW1 on 25-6-1985 and marked Ex. M1 as a document on behalf of the Management. The workman mentioned that he acted as Munshi in the office for some time and he was incharge of 50 workers as acting Munshi since 28-7-1981 though he worked as Trammer in the Singareni Collieries since 1952. He asserted that he was continuously working from 28-7-1981 till 10-5-1985 and he was having pay slip that he received

as acting allowance during that period. The witness infact produced pay slip and wanted to file them properly. He asserted that the post in which he was acting was a clear vacancy and he has to be absorbed in it permanently as per Standing Orders from 28-7-1981 onwards with attendant benefits. According to him he admitted in the cross examination done by the management counsel that Yellandu, Manuguru and Kothagudem will be considered as one area for the purpose of seniority of employees including Trammers and there are Trammers working in Yellandu, Manuguru and Kothagudem. He conceded that he is not the senior-most trammer in the area and Regional i.e. Yellandu, Manuguru and Kothagudem. But at the same time he did not know to give promotion from a Trammer to Munshi post the senior-most Trammer will be considered for the said post. He denied the suggestion that he is not entitled for the post of Munshi as he is not the senior-most Trammer among the area and that the promotional policy of the Management observe only seniority as criteria for such promotion. He admitted that under Ex. M1 the senior-most Trammer of the Area will be given opportunity to be posted as Munshi. But he explained that he did not know by the time whether by that time they called for seniority list of Trammers or not. But it is his case that one C. Narasiah, permanent munshi was medically declared unfit for promotion and the post became vacant and denied about the promotional policy. It is his case that he joined in the Company in the year 1952 and denied the suggestion that he was appointed as Trammer on 1954.

6. After the evidence is over on 25-6-1985 for workman it is posted for Managements evidence on 31-7-1985 and it was being adjourned from time to time and they took time till 29-8-1985 and 30-9-1985 and they filed a Memo finally on 10-12-1985 stating that they are reporting settlement and that the talks are going on between the Union and the Management to arrive at a settlement. Again on 1-4-1986 there was such a Memo stating that negotiations to settle the matter out of Court was going on and sought for adjournment for two months. After 1-4-1986 the matter was adjourned to 30-5-1986, 1-8-1986, 25-8-1986, 10-9-1986 and 22-9-1986 but still no settlement is filed and the management also given one more chance to adduce evidence from 10-9-1986 to 22-9-1986 to produce their evidence for filing the said settlement in the matter. They did not file any settlement. In fact they filed a Memo on 10-9-1986 stating that they are not proceeding further in the matter as they are moving application for transfer of their cases as petition filed in I.D. No. 41 of 1985. But no such transfer order was received in this matter at any time stating this matter is stayed. There is no representation from authorised representative to that effect. The Tribunal had occasion to pass an order in M.P. No. 278/86 in I.D. No. 41 of 1985 on 4-9-1986 and the Memo was also rejected. Both the matters have no connection at all. They are not common issues also.

7. The interesting facts in this case are after having taken time to produce settlement from the time the workman's evidence was closed on 25-6-1985 for more than 1-1/2 years. The Management could not bring forth the so called negotiated settlement with the workers and they could not adduce evidence on their part to substantiate their promotional policy. Further they did not indicate that there were number of seniors and by virtue of the said promotional policy. Further they did not indicate that there were number of seniors and by virtue of the said promotional policy that so and so were posted in his place. It is not denied that K. Suryanarayana was working as Munshi in Grade III in the place of C. Narasiah from 28-7-1981 and he continued to work so till 10-5-1985. Now if there is a promotional policy for filling up the vacancies from Trammer to Munshi as per Ex. M1 there must be clear date to show that XY or Z who is working at Yellandu, Manuguru and Kothagudem who were seniors to K. Suryanarayana were called for interview in view of the so called promotional policy and they were given the said posting. Infact Ex. M1 would show that in Clause 4 as follows: "In the light of past experience it has now been decided to adopt the following procedure for promotion to Grade II and Grade III Munshis, and that the Trammings Muscadams may be taken separately for each area of Kothagudem, Bellampalli

and Ramagudam Area I and II) as one Unit for promotion to Grade II Munshis and Grade III Munshis respectively in the respective areas". So far Grade III Munshis from Training Muccadams separately from each area heading each as one unit by itself to be considered for promotional policy is quite contrary to the promotional policy suggested to the witnesses. Moreover vaguely stating that there are some seniors to him will not give a right to the Management to show that mere seniority is the criteria for promotional policy. At any rate the experience of this K. Suryanarayana as acting munshi from 26-7-1981 to 10-5-1983 in a clear existing vacancy would show that he had gained experience in the higher post of munshi and thus he had acquired better qualifications or supervisions and he was able to do the job satisfactorily to the satisfaction of his superiors and the Management could not file any complaints during the period of four years that the said K. Suryanarayana was not able to perform the duties of Munshi or that he acted contrary to the Standing Orders or the job requirements of a Munshi. There is no such evidence forthcoming. So if the promotional policy is only based upon seniority they should not have allowed K. Suryanarayana to act in a clear vacancy without calling the seniormost people whose data is available with the Management and when it is their case that after one week after he was kept incharge they tried to call for the seniormost Trammer from the three areas. If it is really correct they could have displaced K. Suryanarayana by the seniormost Trammer either from Yelianou, Manuguru or Kothagudem and the Management did not require four years to implement their promotion policy based upon mere seniority. It is ridiculous to say that seniority is only the criterion in a given circumstances like this when K. Suryanarayana was already acting continuously for four years as a Munshi in a higher category drawing acting allowance when compared with others. Section 2(1) of the Standing Orders directly apply to such a case and when he is continuously working as a Munshi for four years to say that he is only a Trammer and because he is paid acting allowance without being confirmed he should face the interview and he cannot be called for interview on the ground that there were seniors to him seems to be rather violation of Rule 2(1) of Standing Orders as no workers should be kept acting for a long time when there is a clear vacancy without filling it properly when the workers is discharging his duties continuously for four years, it is incorrect to say that he is only acting and that he cannot be construed as a permanent employee in that acting category or post. The Management's attitude in dragging on the proceedings for over 1-1/2 years without any evidence on the pretext of negotiations being conducted would show that the seniority for Grade III Munshis from Training Muccadams was being taken separately of each area of Kothagudem, Bellampally and Ramagudam and therefore they were in a very difficult fix to explain their own so-called promotional policy and the so-called alleged promotional policy was not implemented and it was not even brought to the notice of the workers and the Management cannot contend that it is managerial function when it affects the rights of the workers that they can frame their own promotional policies without consulting the workers who are affected parties. Moreover it need not be stressed as per the Industrial Dispute Act a workers case should be disposed of in a stipulated time of three months from the date of reference, if it is an individual case or within period of six months if it is a case involving more than one worker and looked from any angle this kind of delay without any explanation would only add misery to the worker who is involved in this reference while the Management is quite happy in dragging the proceedings for reasons best known to them. So taking all these matters into consideration and also evidence of W.W1 and also Ex. M1 and the attendant circumstances as discussed supra, I hold that the Management of Singareni Company Limited was not justified in not calling Kudipudi Suryanarayana who was acting Munshi with effect from 28-7-1981 for selection to the post of Munshi on regular basis and not confirming him as Munshi. On a clear understanding of the Standing Orders as well as the clear evidence placed before me I hold that he was continuously acting for more than four years from 28-7-1981 and that he is entitled for being selected for the post of Munshi on a regular basis and also for confirmation as Munshi as per the Standing Orders, and therefore the said

Sri Kudipudi Suryanarayana is entitled for confirmation from 28-7-1981 with attendant benefits as Munshi.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the fourth day of October, 1986.

Sd/- Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witness Examined

for the Workmen:

W.W1 K. Suryanarayana

Witnesses Examined
for the Management

NIL

Documents marked for the workmen

NIL

Documents marked for the Management:

Ex. M1 True copy of the letter dt. 2-8-76 addressed to all Additional General Managers and all Divisional Superintendents (Kothagudem) by the General Manager S. C. Company Limited, Kothagudem with regard to filling up of vacancies of training munshis.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. I-22012/109/83-D.III(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का भा 3891:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेवडोरेस/क्लोयर्सिंग एंड फार्वर्डिंग एजेंट्स, काट्टैकर्ट्स के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में माहयस्यों के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27 अक्टूबर, 1986 का प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3891.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the award of Arbitrators as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Stevedores/Clearing and Forwarding Agents/Contractors and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th October, 1986.

IN THE MATTER OF ARBITRATION UNDER SECTION 10-A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, RELATING TO QUANTUM OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO UNLISTED WORKERS AND THREE OTHER ISSUES BETWEEN THE PARADEEP PORT STEVEDORES ASSOCIATION, PARADEEP PORT, ORISSA AND PARADEEP PORT & DOCK MAZDOOR UNION,

PARADEEP PORT, ORISSA

BEFORE SHRI P. D. SHENOY AND SHRI H. G. BHAV
JOINT ARBITRATORS

FOR THE EMPLOYERS:

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.
A. Suba Rao
- 2 M/s. J. M. Baxi & Co.
K. Ramiah
3. M/s. L. M. Hati & Co.
S. C. Hati

4. M/s. S. C. Das & Co.
B. Das
5. M/s. E. C. Bose & Co.
K. J. Valson
6. M/s. T. P. Roy Choudhury & Co.
Balaram Khuntia
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.
Mahimananda Mishra
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd
A. Pattanaik
9. M/s. Mahima Nanda Mishra
P. K. Hati
10. S. P. Nanda, Advocate
11. B. M. Patnaik, Advocate.

FOR THE WORKMEN :

1. G. S. Jena, President
2. A. C. Nag, Vice-President
3. Dulal Nath, Vice President
4. C. K. Mahapatra, Joint Secretary
5. Babaji Ch. Swain, Orgn. Secretary
6. A. K. Swain, Orgn. Secretary.

Representative of Paradeep Port & Dock Mazdoor Union
Paradeep Port, Orissa.

AWARD

4. Under an agreement between the management of Paradeep Port Stevedores Association, Paradeep Port on behalf of all Stevedores, clearing and forwarding Agents, contractors of Paradeep Port, Orissa and their workmen represented by the Paradeep Port and Dock Mazdoor Union. Paradeep Port signed on 29th January, 1985 in terms of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947, the dispute between them regarding the Quantum of House Rent Allowance to unlisted workers, payment of wages to unlisted workers in terms of National Wage Settlement dated 4-1-1981 and 11-4-1984, method of working out daily wage to unlisted cargo handling workers and payment of attendance allowance to unlisted cargo handling workers, was referred for our joint arbitration. The Government of India, Ministry of Labour in accordance with the provision of sub-section (3) of Section 10-A of Industrial Disputes Act, 1947 ordered the publication of the said agreement vide order No. L-38012/2/85-D-IV(A), dated 18-3-1985.

2. The specific matters in dispute as referred for our arbitration were worded as follows :—

- “1. Quantum of House Rent Allowance to unlisted workers.
2. Payment of Wages to unlisted workers in terms of National Wage Settlement dated 4-1-1981 and 11-4-1984.
3. Method of working out daily wage to unlisted Cargo Handling Workers.
4. Payment of Attendance Allowance to unlisted Cargo Handling Workers.”

3. The parties to the dispute were requested vide letter dated 27/29th March, 1985 to file their statement of the case in triplicate within 15 days from the date, endorsing a copy of the same to the opposite party simultaneously. The parties requested for extension of time for filing their written statement which was granted by us upto 25-4-1985 vide letter dated 19-4-1985.

4. On receipt of the complete papers from the parties concerned, the parties were called for a personal hearing on 21-8-1985 at Bhubaneswar and were also requested to come with all evidence, oral or documentary substantiating their case. The parties were given personal hearing on 21-8-1985. Employers filed their rejoinder dated 20-8-1985 on 21-8-1985. A copy of the same was given to the representatives of Unions to file their rejoinder/reply to the employer's rejoinder. The Union requested for time which

was allowed. The parties were given personal hearing, further on 2-12-1985 at Delhi; 7th and 8th January, 1986 at Bhubaneswar; 17-4-1986 at Calcutta and finally on 30-7-1986 at Delhi. The parties had time to time mutually extended the time to give our Award and finally on 17-4-1986, the parties gave their consent extending the period for release of the Award upto 31-10-1986.

5. On 7th and 8th January, 1986, the parties had detailed arguments over the issues referred to us in this dispute and finally they desired to arrive at mutual understanding by resolving the issues in 3 or 4 sittings which was allowed with the direction to the parties to keep the arbitrators informed about the progress so achieved by them. When the case came up for final hearing on 30-7-1986, the parties in disputes, submitted their joint petition dated 23-7-86 stating that they have arrived at a compromise and have resolved all their dispute/differences including the specific matters pending before us in this dispute and requested us to accept this agreement and pass an order in terms of their agreement dated 23rd July, 1986. They filed copies of their mutual agreement dated 23rd July, 1986 which have been taken on record and annexed to this Award.

6. During the personal hearing held on various dates, the parties had submitted their pleadings and documents in support of their claims which do not now call for any examination or discussions. The mutual agreement dated 23-7-1986 filed before us has however, been examined by us and we find that the agreement is a package deal on various issues including inter alia the four demands referred to us. This agreement is fair and just. We are of the opinion that this agreement would be in the better interest of the workmen to set at rest their claims in question.

7. We therefore, give this award on the terms, which have been agreed upon between the parties in the agreement dated 23rd July, 1986 which now form part of this award.

8. We are highly thankful to the parties for the whole hearted co-operation extended to us by them during the arbitration proceedings.

(H. G. BHAVE)

Joint Chief Labour Commissioner (C) &
Arbitrator

(P. D. SHENOY)

Chief Labour Commissioner (C) &
Arbitrator

New Delhi :

Dated : 15th October, 1986.

BEFORE

Sri P. D. Shenoy,
Chief Labour Commissioner (Central),
New Delhi.

Sri H. G. Bave,
Jt. CLC (Central),
New Delhi.

...Arbitrators

In the matters of :

Reference No. 8 of 1985

(Arbitration under Section 10A of the I.D. Act, 47)

AND

In the matter of Government of India Order No. D/19-3-85.

AND

In the matter of Arbitrator Agreement, dated 21-1-1985.

BETWEEN

C&F Agents/Stevedores/Contractors of Paradip Port
Represented by President, Stevedores Association—
Employer.

AND

The Workmen Represented by Paradip Port and Dock
Mazdoor Union (INTUC) Paradip Port and Work-
men.

In the matter of Joint Petition of Compromise.
The Petitioners, the Employers and the Union jointly beg
to submit as under :

1. That the aforesaid case is pending before the Hon'ble Arbitrator for their decision.

2. That in the meantime, an amicable agreement has since been arrived at between the Union and the Employer on various issues including the specific issues pending before the Hon'ble Arbitrator in Reference No. 8 of 1985 as per the terms embodied in the enclosed agreement dated 23rd July, 1986.

PRAYER

The Petitioners, i.e., The Union and the Employers jointly therefore Pray that the Hon'ble Arbitrators may kindly accept the said agreement as reasonable and give an Award accordingly.

And for this Act of kindness, the Petitioners shall ever Pray.

SUBMITTED BY :

Employers :

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd, A. Suba Rao.
2. M/s. J. M. Baxi & Co., K. Ramesh.
3. M/s. L. M. Hati & Co., S. C. Hati.
4. M/s. S.C. Das & Co., B. Das.
5. M/s. E. C. Bose & Co., K. J. Valsan
6. M/s. T. P. Roy Choudury & Co., Mr. Balaram Khuntia.
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd., Mr. Mahimananda Mishra.
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd., Mr. A. Pattanaick.
9. M/s. Mahima Nanda Misra, Mr. P. K. Hati.

UNION

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Mr. Dulal Nath | —Vice President. |
| 2. Mr. A. C. Nag | —Vice President |
| 3. Mr. Survamani Swain | —Secretary. |
| 4. Mr. Babagicharan Swain | —Organising Secretary. |
| 5. Mr. Brajabandhu Palta Singh | —Organising Secy. |

Settlement arrived at by agreement between the Stevedores/C&F Agents/Contractors of Paradip and Paradip Port & Dock Mazdoor Union (I.N.T.U.C.) Paradip Port.

NAME OF PARTIES

Representing Employers :

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.,
2. M/s. J. M. Baxi & Co.,
3. M/s. L. M. Hati & Co.,
4. M/s. S. C. Das & Co.,
5. M/s. E. C. Bose & Co., Pvt. Ltd.,
6. M/s. T. P. Roy Chowdury & Co., Pvt. Ltd.,
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.,
8. M/s. Roy & Chatterjee & Co., Pvt. Ltd.,
9. M/s. Mahimananda Mishra.

Representing Workmen :

1. President, Paradip Port & Dock Mazdoor Union.
- 2.

TITLE OF THE CASE

By Order dated 18-3-85, The Government of India in exercise of powers U/s 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputes between Nine Stevedores/Contractors/C&F Agents and 1479 unlisted workers represented by the Paradip Port & Dock Mazdoor Union for Joint Arbitration by the Chief Labour Commissioner, (Central), New Delhi and the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi.

1. Quantum of house rent allowance to unlisted workers.

2. Payment of wages to unlisted workers in terms of National wage settlement dated 4-1-81 and 11-4-84.

3. Method of working out daily wage to unlisted Cargo handling workers.

4. Payment of attendance allowance to unlisted Cargo handling workers.

The said reference registered as Arbitration Case No. 8 of 1985 is now pending adjudication.

In the meantime, several other demands including bonus, etc. for past years have been voiced by the Paradip Port & Dock Mazdoor Union, in short, the Union on behalf of the unlisted cargo handling workers.

The Stevedores/C&F Agents/Contractors as named above, herein after to be shortly referred to as the traders, have taken the stand inter alia in the above Arbitration case and also in their Defence against the subsequent demands as voiced by the above Union that there exists no master-servant relationship between the said Stevedores/C&F Agents/Contractors on the one hand whether jointly or severally and the unlisted cargo handling workers on the other, while the Union has the stand that they are the workers of the said nine employers.

In view of the peculiar system of working by the unlisted cargo handling workers and their development for the clearing and forwarding work undertaken by the traders and without prejudice to the respective stand of the parties as stated above, solely in the larger interest of the Port and its operations and with a view to resolve industrial unrest and frequent stalemates in work, the parties had several rounds of prolonged discussions in mutually to evolve some fairly acceptable solution to all the outstanding conflicts and differences between them and ultimately the following accord has been reached by and between them.

Terms of Settlement :

1. It is agreed that this settlement shall apply to the existing cargo handling workers (unlisted) of the pool in respect of 1479 workers to whom the Paradip Port Trust has issued gate passes as recommended by the pool. In case of such unlisted workers who have in the meantime died their legal heirs certified by the Tahasildar of the respective areas to which the deceased workers belong, shall be paid benefits as contained in clause No. 3 below.

Terms of Settlement :

2. Payment of all moneys under this agreement shall be made through the Paradip Port clearing forwarding and handling workers pool, briefly the pool.
3. It is agreed that all claims/demands/disputes including those pending in Arbitration, claim to bonus, etc., of the workers for the period immediately prior to the date of this agreement shall stand settled by payment of Rs. 2,500 (Two Thousand Five Hundred only) the traders concerned shall collect the above amount from the principals out of levy. The above payment of Rs. 2,500 shall be made in the following manner.

- (i) Each unlisted worker excepting fifty five workers of Iron Ore and Chrome Ore Section shall be paid a lumpsum amount of Rs. 2,500 in five equal instalment of Rs. 500 each per quarter, with the first such quarterly payment to be alongwith the monthly wages (earnings) for July, 1986.

- The above said fifty five workers of Iron Ore and Chrome Ore Section shall be paid Rs. 2,000 (Two Thousand Only) as they have already been paid bonus/ex-gratia for two years payable on the line indicated above.

- (ii) It is understood and agreed that the above payment shall not attract any legal liability in respect of provident fund and gratuity.

(iii) The Pool will be requested by the parties jointly and severally to immediately intimate each of the trades and the Union the names of unlisted workers who have received such ex-gratia sum.

(iv) It is agreed that with effect from the date of this agreement, each unlisted worker drawn from the pool by any of the traders shall be paid the rates of wages as per Annexure-I to this agreement which has been formulated keeping in view the various wage settlements between the Government of India and the Federation of Unions of Port and Dock Labour and the present practice in the Paradip Port. It is understood and agreed by and between the parties that the term (wages) in the context of this agreement shall include basic Pay, DA, VDA, S.D.A. House Rent Allowance, Off-Day Wages, National and Festival Holidays wages, Attendance Allowance and Computation of Daily wages dividing basic monthly pay by 26 days and other components by 30 days.

Provided that, the amount of bonus/exgratia as agreed in Annexure-I will accumulate with the pool and will be released for payment to the concerned workers alongwith the earnings of the Month of September, 1986.

And thereafter the amount of bonus/exgratia shown in Annexure-I shall be paid alongwith their monthly wages.

Provided that, in respect of ancillary workers, (unlisted) drawn by the traders from the pool, the payment of wages shall be at the same rate as will be paid by the Port Trust authorities to their ancillary workers, and in case the ancillary workers of the Port Trust become entitled to any retrospective increase in wages as per the pending Arbitration Case No. 9/85 from a date prior to the date of this agreement, the traders shall pay in respect of the ancillary workers such increased rate only with effect from the date of this agreement.

(v) The above wage fixation shall remain in force until the next settlement between the Government of India and the federations of the major Port and Dock workers.

(vi) It is agreed that the itemwise datum and the incentive scheme as indicated in Annexure-II shall be scrupulously followed by the workmen in case the output falls below the datum where the work is available, the concerned workmen shall be entitled to wages only at the prorata basis (Tonnage rate) as stipulated in Annexure-II.

(vii) It is understood and agreed that the pool shall not give booking to any worker for more than two duties in a day and that deployment of mazdoors and sardars shall not depend upon availability or non availability of Supervisors till the time the Union submits to the pool a list of educated workers for consideration of promotion as supervisors.

(viii) It is agreed that the parties will take up with the pool for increasing its efficiency for more effective control of Labour and for an equitable distribution/allocation of Labour to the traders as per requirement.

(ix) It is agreed that in case any worker misconducts himself while working for any trader, the concerned trader will be free not to accept his booking for a period of maximum 7 (seven) days with issuance of a letter to the pool informing the nature of misconduct of the worker immediately with a copy to the concerned Union and the other traders will also be free to refuse acceptance of his booking for any of them for the above period of seven days. An enquiry shall be made jointly by the representatives of the complaining, traders & representative of the concerned Union and representative of the pool in presence of the worker within the said seven days. In case of absence of either of the two parties other than the complaining trader the result of the enquiry by the two parties shall be final. If the concerned worker is found to be not guilty, the complaining trader shall be liable to deposit his wages with the pool of his bookings lost under the said trader.

Provided that the above arrangement shall cease to operate on the coming into force of a code of conduct for the workmen for which the parties hereby agree that they would

approach the pool within a period of two months with a commonly accepted draft code of conduct for adoption and execution by the pool.

(x) The parties understand and agree that in the event of future decasualisation of the unlisted Labour/Workmen, this agreement shall not stand as bar.

(xi) The parties understand and agree that during the currency of this agreement, there shall be no other or further demand involving financial commitments from the traders in respect of the matters covered by this agreement.

(xii) This agreement shall come into operation from the date of signing of this agreement i.e. 23rd July, 1986 and shall be operative until the next settlement between the Government of India and the Federation of Major Port & Dock Workers.

(xiii) Since the parties have resolved all their disputes/differences including the specific matters pending before the learned Arbitrators in Arbitration Case No. 8 of 1985, the parties agree and undertake to approach the learned Arbitrators to accept this agreement and pass an Award in terms thereof.

In witness whereof the Parties through their Authorised representatives put their hand and seal to this agreement this day of 23rd July, 1986.

REPRESENTATIVES OF TRADERS :	UNION REPRESENTATIVES OF PARADIP PORT & DOCK MAZDOOR UNION
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------

1. M/s The O.S.C.T.C. Ltd. Sd/- (A. SUBA RAO)	Sd/- 1. A.C. NAG, Vice President.
2. M/s J.M. Baxi & Co. Sd/- (K. RAMESH)	Sd/- 2. Dulal Nath, Vice-President.
3. M/s L.M. Hati & Co. Sd/- (S.C. HATI)	3. Surya Mani Swain Secretary.
4. M/s S.C. Das & Co. Sd/- (B. DAS)	4. Babaji Ch. Swain Organising Secretary.
5. M/s F.G. Bose & Co Sd/- (K.J. WALSON)	5. Brajabandhu Palta Sing. Organising Secretary.
6. M/s T.P. Roy Choudhury & Co. (P) Ltd Sd/- (B. KHUNTIA)	WITNESSES :
7. M/ Oriana Stevedores (P) Ltd Sd/- (Mahimnanda Mishra)	(1) Signature . Name in Capital Letters. Address : Basanta Kr. Bala P.O. Aripada V, Narahri Pur. P.S. : Kendrapara.
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd. Sd/- (A. Patraaik)	DL. Curtack. (2) Signature Name in capital letters Address :
9. M/s. Mahimnanda Mishra Bania Sahi Sd/- (P.K. HATI)	Cuttack-753001 (Mana Mohan Noharana)

ANNEXURE—I

Category	Daily Wages including allowances as mentioned in agreement D/23-7-86 under Item No. 3 (IV)	Daily Rate of Bonus/Exgratia	Daily Wages (Gross) Total
1	2	3	4
Supervisor	Rs. 57.63 ps.	Rs. 4.80 Ps.	Rs. 62.43 Ps.
Sardar	Rs. 53.43 ps.	Rs. 3.99 Ps.	Rs. 57.42 Ps.
Mazdoor	Rs. 52.03 Ps.	Rs. 3.87 Ps.	Rs. 55.90 Ps.

N.B. The above wages have been calculated keeping in view of the scale of pay being paid to the above categories by the Paradip port trust as per the wage board recommendations D/11-4-84.

No further wages revisions will take place during the currency of Agreement D/23-7-86, Vide Clause Nos. 3(xi) & (xii)

EMPLOYERS		UNION
1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.	—A. Suba Rao	1. Dulal Nath, Vice President
2. M/s. J.M. Baxi & Co.	—K. Ramesh	2. A.C. Nag, Vice President
3. M/s. L.M. Hati & Co.	—S.C. Hati	3. Surmani Swain, Secretary
4. M/s. S.C. Das & Co.	—B. Das	4. Babaji Charan Swain, Organising Secretary
5. M/s. E.C. Bose & Co.	—K.J. Valsan	
6. M/s. T.P. Roy Choudhury & Co. P. Ltd.	—B. Khuntia	5. Brajabandhu Paltasingh Organising. Secretary.
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.	—M.N. Mishra	
8. M/S. Roy & Chatterjee (P) Ltd.	—A. Pattnaik	
9. M/s. Mahimananda Mishra	—P.K. Hati	

ANNEXURE—II

Statements of Datum and Rates/Incentive Rates thereof Fixed PER M.T. for Different types of Cargos of at part of Parlip

S. No.	Cargo	Gang strength	Datum (per gang per shift)	Time/Rate per M/T.	Incentive			
					Up to 50 % of above datum		over 50 % of above Datum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Bag Cargo	8—1	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	Per M.T.	Rs. 13.00	Per M.T.
2. Drum	8+1	30.00 M.T.		Rs. 14.00	Rs. 15.00	-do-	Rs. 16.00	-do-
3. Bale	8+1	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	-do-	Rs. 13.00	-do-
4. Cooking Coal/Hard Coke/Coastal coal	8+1 U/L (By Wagon)	30.00 M.T.		Rs. 14.00	Rs. 15.00	-do-	Rs. 16.00	-do-
5. Iron Ore	8+1 ..	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	-do-	Rs. 13.00	-do-
6. Pig Iron	8+1 ..	32.00 M.T.		Rs. 13.10	Rs. 14.00	-do-	Rs. 15.00	-do-
7. Bulk (Iron Ore/Chrome Ore)	8+1	100.00 M.T. (U/L) Truck		Rs. 4.20	Rs. 4.50	-do-	Rs. 4.85	-do-
Ferro Maganese/Manganese Ore.	8+1	50.00 M.T. (L) Truck		Rs. 8.40	Rs. 9.00	-do-	Rs. 9.70	-do-
8. Charge Chrome	8+1	70.00 M.T. (U/L) Truck		Rs. 6.00	Rs. 6.40	-do-	Rs. 6.90	-do-
	8+1	50.00 M.T. (L) Truck		Rs. 8.40	Rs. 9.00	-do-	Rs. 9.70	-do-
9. Copper Concentrate	8+1	65.00 M.T. (U/L) Truck		Rs. 6.45	Rs. 6.90	-do-	Rs. 7.50	-do-
	8+1	50.00 M.T. (L) Truck		Rs. 8.40	Rs. 9.00	-do-	Rs. 9.70	-do-
10. Steel Billets & Wire Rod	8+1	118.00 M.T. L or U/L by Crane		Rs. 3.35	Rs. 3.80	-do-	Rs. 4.15	-do-
11. Steel Sheet Coil & Steel Slab up to 9 M.T. per pc	8+1	23 Pcs L or U/L By crane (207-MT)		Rs. 18.25 Per pc. or Rs. 2.05 per MT.	19.50 Per pcs 2.15 per MT.	Rs. 21.20 Per pcs or Rs. 2.35		

	2	3	4	5
12. Steel Slab/Coil of 25 M.T.	8 + 1	16 Pcs L or U/L by Crane (400 M.T.)	Rs. 26.25 per pcs. or Rs. 1.05 per MT.	Rs. 28.25 per pcs. or 1.15 Per MT.
(Weight Above 9 MT. upto 24 MT. Tonnage rate will apply)				
13. Steel-wire rod coils bounding (Minimum 4 Stings each boundle)	8 + 1	44 boundles	Rs. 9.55 per Bdl.	Rs. 10.55 Per Bdl.
14. Hard Coke	8 + 1 U/T	80 M.T.	Rs. 5.25 Per MT.	Rs. 5.75 Per MT.
	L/T	30 M.T.	Rs. 14.00 -do-	Rs. 15.00 Per MT.

- Note.—(1) The output of the shift shall be as per the Tally maintained by the Pool supervisor and certified by user supervisors.
 (2) In view of the present piece rate scheme there will not be any payment of any nature for increasing output arbitrarily when the actual output is less for the deliberate slowdown of work, the gang will be paid reduced wages pro-rate.
 (3) If it is so required by the user, the gang booked for a particular spot will be shifted to any other work spot within the port to enable the user to provide sufficient work to meet datum requirement.
 (4) In the case of any eventuality, the user would be within his right to change the type of work contemplated originally for the gang—viz. L to U/L, Truck loading to wagon Loading vice-versa etc. which will be restricted to one changing.

EMPLOYERS

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.—A. Subu Rao
2. M/s. J.M. Boxi & Co. —K. Ramesh
3. M/s. L.M. Hati & Co. S.C. Hati
4. M/s. S.C. Das & Co.—B. Das
5. M/s. E.C. Bose & Co.—K.J. Valsan
6. M/s. T.P. Roychoudhury & Co. (P) Ltd. B. Khuntia
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.—M.N. Mishra
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd.—A. Pattnaiak
9. M/s. Mahimananda Mishra—P.K. Hati

UNION

1. Dulal Nath, Vice President
2. A.C. Nag, Vice President.
3. Suryamani Swain, Secretary
4. Babaji Charan Swain, Organising Secretary
5. Brajabandhu Palasingh, Organising Secretary

[No. L 380 13/2/85/D. IV(A)]

K. J. DYVAPARSAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

Dated, Dhanbad, the 16th October, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(80)/85-D. III(A), dated, the 30th July, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in denying employment to the dependant of Smt. Anjwa Chamarain, ex-Wagon Loader as per the provisions of National Coal Wage Agreement is justified? If not, to what relief the dependant of the said workman is entitled?"

The case of the workmen is that Anjwa Chamarain was a permanent wagon loader in West Mudidih Colliery of M/s. B. C. C. Ltd. She was residing in a hut on the management's land and materials for construction of the said hut were supplied by the management as no quarter had been provided to her. The said hut caught fire due to which the hut was burnt and Anjwa Chamarain was also badly burnt in the said fire. The said burning injury caused to her permanent disablement. Anjwa Chamarain represented before the management for giving employment to her dependant son Nunu Ram who was her adopted son under the provision of NCWA-II. The management also declared Anjwa Chamarain as disabled workman on the basis of the report of the medical board dated 14-8-82. When her prayer was not allowed, she represented Bihar Janta Khan Mazdoor Sangh the union who raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad. After the failure of the conciliation before the ALC(C) the dispute was referred for adjudication to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour. It is further submitted that Anjwa Chamarain was married

का.मा. 3892—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की पश्चिम मुदीदीह कोलियरी के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवर्ष में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3892.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 113 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of West Mudidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen: Shri S. N. Bhattacharva Advocate and Shri S. N. Goswami, Advocate.

On behalf of the employers Shri B. Joshi, Advocate

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

to Sukhdeo Das. Anjwa Chamarain was issueless and as such she and her husband Sukhdeo Das jointly adopted Shri Nunu Ram and the said adoption was given to them by the natural parents of Nunu Ram. Subsequently a deed of adoption dated 29-3-82 was executed by Anjwa Chamarain and Kaila Devi the natural mother of Nunu Ram. It is further submitted on behalf of the workmen that under para 10.4.3 of NCWA-II Anjwa Chamarain is entitled to the employment of her dependent Nunu Ram when she adopted as her son.

The case of the management is that Anjwa Chamarain, wife of Sukhdeo Das, joined as Casual wagon loader at West Mudidih Colliery on 11-6-75. She left her employment from 27-12-81. She submitted her resignation letter dated 23-9-82 and the same was accepted by the management on 8-10-82. According to the management, Anjwa Chamarain left her employment at her own accord on 27-12-81 and the subsequent submission of her resignation dated 23-9-82 was with some ulterior motive. She had submitted a photo copy purported to be a deed of adoption dated 29-3-82 indicating that she had adopted Nunu Ram aged 23 years and she had requested the management to give employment to Nunu Ram as her dependent. The concerned lady had left her employment on 27-12-81 and had prepared a deed of adoption on 29-3-82 at the instance of certain interested persons on payment of certain considerations for the purpose of giving employment to Nunu Ram. Her claim was mala fide and not a genuine claim for employment of Nunu Ram. The deed of adoption was invalid as Nunu Ram the person purported to have adopted was aged 23 years at the time of the execution of the adoption deed. She had no legal right to claim for employment of the adopted son after having resigned from service. The management had not provided any material for the construction of nut of Anjwa Chamarain. The management was not aware of the alleged accident due to which Anjwa Chamarain was burnt. The concerned lady had submitted her resignation voluntarily after leaving her employment. The case of termination of her services due to her permanent disablement was not true and it was concocted to secure employment to a stranger. On the above plea it is submitted on behalf of the management that Anjwa Chamarain is not entitled for the employment of Nunu Ram as her adopted son.

The only point for consideration in this case is whether Anjwa Chamarain is entitled to get employment of Nunu Ram as her dependent being her adopted son.

The management examined one witness and the workmen have examined three witnesses in support of their respective cases. The management has got 4 documents exhibited which are marked Ext. M-1 to M-4. The workmen's documents have been marked Ext. W-1 to W-3.

Admittedly Anjwa Chamarain was a permanent wagon loader in Mudidih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. It will appear from the evidence of MW-1 Shri Birendra Singh working as Senior Personnel Officer in West Mudidih Colliery that the medical board had reported Anjwa Chamarain unfit. In the cross-examination he has stated that the medical report by which the concerned lady was declared unfit by the management is in the office of the management and the same can be filed. It is thus clear from the evidence of the management's witness that the concerned lady Anjwa Chamarain had been declared medically unfit and that the management possesses the said medical certificate. WW-1 is Anjwa Chamarain herself. She has stated that in December, 1981 the electric line fell on her hut causing fire to her hut, and also causing burning injuries to her. She has stated that she was taken to Lovabad hospital where she remained as an indoor patient for about a fortnight. She further stated that she was disabled due to the said injury. It is thus clear from the evidence of MW-1 and WW-1 that Anjwa Chamarain was declared unfit by the medical board.

Ext. M-3 dated 23-9-82 is a petition filed by Anjwa Chamarain to the Manager, West Mudidih Colliery in which it is stated that she has resigned from her service for giving employment to her adopted son Nunu Ram. She stated in that petition that she had become medically unfit and was declared

unfit by the medical board and as such she demanded that her adopted son Nunu Ram may be given employment under the provision of NCWA-II. Ext. M-4 dated 8-10-82 is a letter by the Manager, West Mudidih Colliery in reply to Ext. M-3 by which the management refused to give employment to Nunu Ram as the dependent adopted son of Anjwa Chamarain. It is also stated in this reply that the medical board after her examination had found that she was not fit for work and as such her resignation was being accepted with effect from 11-10-82. Thus this letter Ext. M-4 also shows that Anjwa Chamarain had been declared unfit and disabled by the medical board of the management and as such her resignation was accepted by the management.

Ext. W-1 is the deed of adoption dated 29-3-82 executed by Anjwa Chamarain adoptive mother and Kaila Devi the natural mother of Nunu Ram. The adoption deed appears to be very badly drafted. It is stated in the deed that Anjwa Chamarain has no natural born or daughter of her own and there is no chance of having any issue because of her health and age thus she is desirous to adopt a son who should perform necessary and usual ceremonies after her death to afford peace to her soul. It is further stated that Kaila Devi mother of the adopted son was willing to give her son Nunu Ram aged about 23 years to her for adoption on 7-3-78. It is further stated that she had already adopted Nunu Ram as her son with the consent of Kaila Devi and also with the consent of Nunu Ram. It will thus appear from the adoption deed Ext. W-1 that Nunu Ram was adopted when he was aged 23 years and that the natural mother Kaila Devi had given consent for the said adoption and that Nunu Ram had also given his consent for being adopted as the son of Anjwa Chamarain. Ext. W-2 is the affidavit of Sukhdeo Das and Anjwa Chamarain dated 26-6-84 and Ext. W-3 is the affidavit of Kaila Devi of the same date. It will appear from Ext. W-2 that both Sukhdeo Das and Anjwa Chamarain had adopted Nunu Ram and were the adoptive parents. It is further stated by them that they had verbally adopted Nunu Ram at the age when Nunu Ram was aged three years and thereafter they prepared an agreement of adoption on 7-2-78 and lastly prepared a registered deed of adoption on 29-3-82. Kaila Devi in her affidavit Ext. W-3 has stated that her son Nunu Ram was brought up by the adoptive mother Anjwa Chamarain and adoptive father Sukhdeo Das. She has stated that she gave Nunu Ram in adoption to Anjwa Chamarain and Sukhdeo Das. It will thus appear from the affidavit that Nunu Ram was the adopted son of both Anjwa Chamarain and her husband but the deed of adoption shows that the adoption had been made by Anjwa Chamarain alone and as such she had executed a deed of adoption. No evidence of reliable independent person has been produced to show that Nunu Ram had been adopted at the age of 3 years. On the contrary the evidence of WW-1 and WW-2 is that the adoption took place about 15 years ago. It will appear that WW-3 Nunu Ram who is said to be adopted son of Anjwa Chamarain is aged 24 years. Thus the adoption according to the workman took place about 21 years ago. The evidence of WW-1 and WW-2 that the adoption took place about 15 years ago does not find support from the evidence discussed above. Under Section 16 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 it is provided that when ever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provision of this Act unless and until it is disproved. There is already a registered deed of adoption Ext. W-1 and there is presumption in favour of the adoption.

We have therefore to see whether the adoption supported by Ext. W-1 has been disproved by the management. WW-1 Anjwa Chamarain has stated in her evidence that Madho Ram and his wife gave their child Nunu Ram in adoption to Anjwa Chamarain and her husband. She has stated that subsequently her husband Sukhdeo married Shanti Chamarain and out of the said marriage Sukhdeo had two sons named Mahes and Bijoy and a daughter Usha. She has admitted that she had nominated Bijoy son of Sukhdeo for the purpose of gratuity and Provident Fund. Ext. M-1 is the declaration by Anjwa Chamarain in respect of the C.M.P.F. which shows that she

had nominated Bijoy Das for the purpose of withdrawing the amount of her P.F. in case of her death. She has described Bijoy Das as her son aged 10 years. Thus it appears from Ext. M-1 that Anjwa Chamarain had nominated Bijoy Das as her nominee for the purpose of P.F. In her cross-examination WW-1 has stated that in all the nominees filed by her regarding C.M.P.F. gratuity etc. she had given name of Bijoy Das as her son and that after the execution of the deed of adoption in favour of Nunu Ram he has given the name of had adopted Nunu Ram about 15 years ago and since then Nunu Ram as her adopted son for giving employment by the management. It is clear therefore that she had not declared Nunu Ram as her adopted son prior to her deed of adoption Ext. W-1. WW-2 is Sukhdeo husband of Anjwa Chamarain he has stated that he along with Anjwa Chamarain Nunu Ram was residing with Anjwa Chamarain. He has further stated that after the adoption he married Shanti Devi from whom he has two sons Bijoy and Mahesh and a daughter. In his cross-examination he has stated that Bijoy is aged about 7 to 8 years but Ext. M-1 shows that Bijoy Das was aged 10 years when Anjwa Chamarain had nominated him for the purpose of C.M.P.F. There is no date when Ext. M-1 was filled up by Anjwa Chamarain and as such it is not possible to say as to the year when Anjwa Chamarain had described Bijoy Das aged 10 years but this much is certain that he has more than 10 years and WW-2 is not giving the correct age of Bijoy. Sukhdeo Das husband of Anjwa Chamarain has admittedly two sons out of whom one is Bijoy who had been nominated by Anjwa Chamarain as her son in Ext. M-1. Had Anjwa Chamarain adopted Nunu Ram about 15 years ago she would not have nominated Bijoy Das as her son for the purpose of P.F. This Ext. M-1 itself is a settler on the point that Nunu Ram had not been adopted by Anjwa Chamarain prior to nomination of Bijoy Das as her son in Ext. M-1.

Taking the totality of the evidence of the parties it appears clear that Anjwa Chamarain had not adopted Nunu Rma as her son 15 years ago and that the deed of adoption has been executed after she had left her service. It is clear that the said deed of adoption Ext. W-1 and the affidavits Ext. W-2 and W-3 have been created for the purpose of giving employment to Nunu Ram as adopted son of Anjwa Chamarain when she had become unfit for work.

In the result, I hold that the action of the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in denying employment to the dependent of Smt. Anjwa Chamarain, Ex-wagon loader as per the provisions of National Coal Wage Agreement is justified and consequently Nunu Ram, said to be the dependant of Smt. Anjwa Chamarain ex-Wagon loader is entitled to no relief.

This is my Award.

Dated 16-10-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/80/85-D. II (A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

का.प्र. 3893.—केन्द्रीय सरकार, अधक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 4(1) के साथ पठित अधक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946(1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रबल कृतियों का प्रयोग करने हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. श्रम मंत्री, | अध्यक्ष |
| आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद | |
| 2. अधक खान श्रम कल्याण आयुक्त, | उपाध्यक्ष |
| 1-7-145/12, श्रीनिवासनगर, | |
| कालोनी, मुशीराबाद, हैदराबाद-500048 | |

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 3. प्रादेशिक श्रम (केन्द्रीय), | केन्द्रीय सरकार के |
| हैदराबाद। | प्रतिनिधि सदस्य |
| 4. श्री आदिनारायण रेड्डी, | सदस्य |
| विधान सभा सदस्य, हैदराबाद। | |
| 5. श्री जी. भाषकर रेड्डी, | } नियोजकों के प्रति निधि |
| मार्फत-माइका चैम्बर आफ कामर्स, गुदुर, | |
| जिला—नेल्लोर। | |
| 6. श्री एन. सुब्बा रेड्डी, पार्टनर, | } कर्मचारियों के प्रतिनिधि |
| एन एम. रेड्डी, एड कजन, सदस्य, | |
| माइका चैम्बर आफ कामर्स, | |
| 2/191, नर्सिंग राय पेठ, गुदुर, | |
| जिला—नेल्लोर। | |
| 7. श्री के. वेंकट सुब्बा, | } सहाय्य प्रतिनिधि |
| जनरल सेक्रेटरी, माइका भजदुर संघ | |
| कमरा नं. 2071, गुदुर, जिला—नेल्लोर। | |
| 8. श्री बी. राधाध्या, | } सहाय्य प्रतिनिधि |
| बी-175, नवाबपेट, जिला—नेल्लोर। | |
| 9. श्रीमती कलाहस्ती यशोदम्मा, | |
| कल्याण रमा माइका साइन की कर्मकार, | |
| रापुड, तालुक, जिला—नेल्लोर। | |
| 10. कल्याण प्रशासक, | सचिव |
| अधिक कल्याण संगठन, हैदराबाद। | |

2. अधक खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 19 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश की अधक खान श्रम कल्याण निधि की राज्य सलाहकार समिति का मुख्यालय हैदराबाद नियत करती है।

[स.पू.-19012/8/84-उज्ज्व.-II(सी)]

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3893:—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with rule 4(1) of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby constitute an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members for a period of three years from the date of publication of this notification, namely:—

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Labour Minister, | Chairman |
| Government of Andhra Pradesh, | |
| Hyderabad. | |
| 2. Mica Mines Labour Welfare | Vice -Chairman |
| Commissioner, | |
| 1-7-145/12, | |
| Srinivasanagar Colony, | |
| Musheerabad, | |
| Hyderabad-500048. | |
| 3. Regional Labour Commissioner, | Member represent- |
| (Central), | ing Central Govt. |
| Hyderabad. | |
| 4. Shri Adinarayana Reddy, | Member. |
| Member, | |
| Legislative Assembly, | |
| Hyderabad. | |
| 5. Shri D.B. Bhaskara Reddy, | } Employers' repre- |
| C/o Mica Chamber of Commerce, | |
| Gudur, | |
| District Nellore. | |
| 6. Shri N. Subba Reddy, | |
| Partner, | |
| N.S. Reddy & Cousin, | |
| Member, | |
| Mica Chamber of Commerce | |
| 2/191, Narsingraopet, | |
| Gudur, | |
| Distrot, Nellore. | |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7. Shri K. Venkata Subbaiah,
General Secretary,
Mica Mazdoor Sangh,
R. No. 2071,
Gudur,
District Nellore. | } Employee's
representative |
| 8. Shri B. Radhaiah,
B-175,
Nawabpet,
District Nellore | |
| 9. Shrimati Kalahasti Yasodamma,
Worker of Kalyanarama Mica Mine,
Rapur Taluk,
District Nellore. | Woman
representative. |
| 10. Welfare Administrator,
Labour Welfare, Organisation,
Hyderabad. | Secretary. |

2. In accordance with rule 19 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby fixes Hyderabad as the headquarters of the State Advisory Committee for Mica Mines Labour Welfare Fund for Andhra Pradesh.

[No. U. 19312/9/84-W. II(C)]

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1986

का.आ. 3894 :—सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कल्याण आयुक्तों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है जिस का उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए, उनके शीर्षक, उल्लिखित कार्यक्षेत्राधिकार और मुख्यालय होंगे। ये कल्याण आयुक्त उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने संबंधित कार्यक्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मावाहक के रूप में भी काम करेंगे --

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों, दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र |
| 2. कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा | राजस्थान, गुजरात और हरियाणा |
| 3. कल्याण आयुक्त, कर्मा | बिहार |
| 4. कल्याण आयुक्त, नरनरवर | उड़ीसा |
| 5. कल्याण आयुक्त, जबलपुर | मध्य प्रदेश |

[स. एस.-22025/3/86-कल्याण-4]

New Delhi, the 6th November, 1986

S.O. 3894 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act,) the Central Government hereby appoint the following Welfare Commissioners with jurisdiction and Headquarters indicated against each for the purpose of the said Act and the Cine-Workers, Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. These Welfare Commissioners will also act as Head of the Departments to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare

schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of their respective jurisdiction—

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Welfare Commissioner,
Allahabad. | Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Union Territories of Delhi and Chandigarh. |
| (2) Welfare Commissioner,
Bhilwara. | Rajasthan, Gujarat and Haryana. |
| (3) Welfare Commissioner,
Karma. | Bihar. |
| (4) Welfare Commissioner,
Bhubaneswar. | Orissa. |
| (5) Welfare Commissioner,
Jabalpur. | Madhya Pradesh. |

[S./22025/3/86-W-IV.]

का. आ. 3895 :—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 18 नवंबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 106/5/85-एफ(1) के अधिक्रमण में कल्याण आयुक्त, नागपुर को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य तथा गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्षेत्राधिकार होगा। कल्याण आयुक्त, नागपुर उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मावाहक के रूप में भी काम करेगा।

[एस-22025/3/86-कल्याण-4]

S.O. 3895.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification No. 106/5/85-F(I) dated the 18th November, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Nagpur with the jurisdiction of the State of Maharashtra and Union Territory of Goa, Daman and Diu for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Nagpur will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S. 22025/3/86-WIV]

का. आ. 3896 :—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण की अधिसूचना संख्या-का.आ. 4963 और का. आ. 4959 के अधिक्रमण में कल्याण आयुक्त, हैदराबाद को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्षेत्राधिकार होगा। कल्याण आयुक्त, हैदराबाद उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मावाहक के रूप में भी काम करेगा।

[एस-22025/3/86-कल्याण-4]

S.O. 3896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification Nos. S.O. 4963 and S.O. 4959, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Hyderabad with the jurisdiction of the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Hyderabad will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

क्र० आ० 3897 —केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं.क्र.आ. 4960 और क्र.आ. 4962 के अधिनियम में, कल्याण आयुक्त, बंगलूर को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए केरल और कर्नाटक राज्यों में कार्य क्षेत्राधिकार होगा। कल्याण आयुक्त, बंगलूर उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

[सं. एस-22025/3/86-इस्यू-4]

S.O. 3897.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification Nos. S.O. 4960 and S.O. 4962, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Bangalore with the jurisdiction of the States of Kerala and Karnataka for the purpose of the said Act and the Cine-

Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Bangalore will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

क्र० आ. 3898 —केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्र.आ. 4961 के अधिनियम में, कल्याण आयुक्त, कलकत्ता को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में कार्यक्षेत्राधिकार होगा। कल्याण आयुक्त कलकत्ता उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा।

[सं० एस-22025/3/86-इस्यू-4]

एम. एस. भल्ला, सचिव

S.O. 3898.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification No S.O. 4961, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Calcutta with the jurisdiction of the States of West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland and Manipur for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Calcutta will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

S. S. BHALLA, Under Secy.

